● वर्ष-4
● अंक-14
रायपुर, सोमवार
26 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जमीन के अंदर शहर चट्टानों में बने...

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक ली

देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा: शाह

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 ज़िलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी भी उपस्थित थे। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 'पीपल फॉर पीपुल' कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 'पैक्स' ने मॉडल बाय-लॉज़ को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राई एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए, जिससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कम्प्यूटराइज़ेशन होने के साथ ही हर 'पैक्स' को सीएससी बना देना चाहिए, जिससे 'पैक्स' द्वारा अनेक गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।

अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और राज्य के बीच अनुबंध होना चाहिए जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत भी कम है और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का अच्छे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए 'पैक्स' द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, 'पैक्स' और सहकारी संस्था का खाता ज़िला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। श्री शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी-फीड इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का, गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके, इसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में कुल 6 ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक हैं और निकट भविष्य में राज्य में 'पैक्स' के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए व्होल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच के तहत राज्य सरकार के पशुपालन, कृषि, जनजातीय मामले और सहकारिता विभागों को मिलकर काम करना चाहिए।

सेक्युलर सिविल कोड पर मुखर मोदी

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करने, आर्टिकल 370, सीएए को समाप्त करने के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों लाल किले से जिस सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था, उसे आज इस कार्यक्रम में फिर दोहराया। मोदी बोलेज्मैंने 15 अगस्त को लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी ज्यूडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है।

उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का उदाहरण, देश के सैंवधानिक एकीकरण का उदाहरण, सीएए जैसे कानूनों का उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्र हित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, यह हमारी अदालतों के निर्णय से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मुद्दों पर अनेक बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम जैसे विषयों को सशक्त किया है।

पीएम ने कहा क आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहित को एडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्यायज्यह भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता हमारे देश को कोलोनियल माइंडसेट से आजाद करवाती है। बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से उपर उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं और देश वासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। जस्टिस फार ऑल इसके लिए उतना ही जरूरी है।

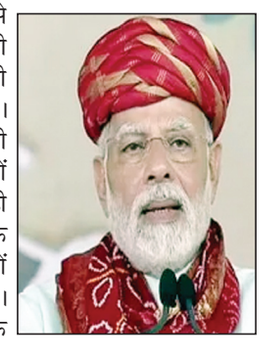

मोदी ने देश में आईटी रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहाज्आईटी रेवोल्यूशन से कितना बड़ा बदला हो सकता है। हमारी ई-कोर्ट्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेशनल ज्यूडिशल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकद्मों की जानकारी एक सेंट्रलाइज प्लेटफार्म पर जुड़ चुकी है। पूरे देश की 3 हजार से ज्यादा कोर्ट 12 हजार से ज्यादा जेलें वीडियो कॉनकॉल से जुड़ गई हैं। मुझे खुशी कि राजस्थान भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पेपरलेस कोर्ट, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कोई सामान्य बदलाव नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री बोलते हुए अचानक रुकेज फिर कहा कि बुरा मत मानना हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द मंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमें का चक्कर, जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। आज उस चक्कर शब्द को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके लिए लगातार हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफार्म करना है। उन्होंने कहा कि आज देश में कम खर्चीले वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की व्यवस्था देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। न्याय पालिका के सहयोग से यह व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त होगी। देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग-अलग काम कर रहे हैं उन सभी का इंटिग्रेशन हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतें एक साथ जुड़कर काम करें। राजस्थान के सभी जिला कोर्ट में इस इंटिग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब के सशक्तिकरण का ट्राइड एंड टस्टेड फार्मूला बन रहा है। सरकार इसके लिए दिशा नाम के इनोवेटिव सोल्यूशन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स लोगों को मिल सके इसके लिए भी काम होने हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है।

आरडीएसओ रिपोर्ट में दावा-रेल हादसों का कारण, कम स्टाफ - काम ज्यादा

नई दिल्ली। लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं रेलवे में हर स्तर पर स्टाफ का अभाव कर्मचारियों का तनाव बढ़ा रहा है। हाल ही में रेलवे के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) की रिपोर्ट में सामने आया है कि ट्रेन कंट्रोलर काफी परेशानियों और चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उनको न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही आराम। नियंत्रण विभाग में लंबे समय से भर्ती न होने से कर्मचारियों पर काम का दबाव और तनाव बढ़ रहा है।

रेलवे बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट में आरडीएसओ ने कहा है कि ट्रेन संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ट्रेन और सेक्शन कंट्रोलरों की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार जरूरी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रोज हजारों ट्रेनें लगभग 1,05,555 किमी लंबे ट्रैक के विभिन्न खंडों से गुजरती हैं। ट्रेन संचालन पर 68 ऑपरेशन केंद्रों द्वारा नजर रखी जाती है। मंडल नियंत्रण कार्यालय से ही ट्रेनों का विभिन्ने रेलखंडों में संचालन होता है। इसलिए यह कार्यालय 24 घंटे काम करता है। आरडीएसओ टीम ने विभिन्न मंडल नियंत्रण कार्यालयों से डाटा जुटाया और पाया कि रेलवे के मंडल नियंत्रण कार्यालयों में 15 से 24 फीसदी तक रिक्तियां हैं।

स्टाफ न होने से काम प्रभावित होता है। किसी कठिन परिस्थिति में तो हालात और खराब हो जाते हैं। वहीं रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों के आराम और छुट्टी के प्रबंधन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए और रिक्ति को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। ॅरिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्शन कंट्रोलर 24×7 काम करते हैं। उनकी शिफ्ट को मानव रहित नहीं छोड़ा जा सकता है। उनको 30 घंटे के साप्ताहिक आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टाफ न होने से उनकी भी साप्ताहिक आराम या छुट्टी की व्यवस्था करने में समस्या होती है। इससे वे थका हुआ महसूस करते हैं और उनका काम प्रभावित होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्शन कंट्रोलर या ट्रेन कंट्रोलर के 75 फीसदी पद पहले स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और ट्रेन क्लर्क के कैडर से भरे जाते थे। मगर सातवें वेतन आयोग में सेक्शन कंट्रोलर का वेतन स्टेशन मास्टर के बराबर कर दिया गया। जबकि पहले यह अधिक था। इसलिए स्टेशन मास्टर संवर्ग ने इस पद के लिए आवेदन करना बंद कर दिया और कैडर में कर्मचारियों की कमी होने लगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में ''पीपुल फॉर पीपल'' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204.84 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। (विस्तृत समाचार पेज 8 पर)

प्रमुख समाचार

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोगली सोच वाली - मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी (सपा) पर रविवार को तंज कसते हुए उन्हें ''दोगली सोच'' वाले दल बताया और लोगों से उनके ''चाल और चरित्र को लेकर सजग'' रहने को कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी सपा एवं कांग्रेस जैसे दलों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक?स' पर लिखा, ''कल (शनिवार) प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते-जी एवं उनके देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।''मायावती ने कहा, ''बाबा साहेब के अभियान को गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम का देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और न ही तत्कालीन सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया।

हिमाचल में पुरानी पेंशन का वादा कब पूरा करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। मोदी सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के यूटर्न वाले बयान पर भाजपा ने जवाब दिया। खरगे ने कहा था कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। इसे लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में किए गए पेंशन के अपने वादे को कब पूरा करेगी? भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि क्या उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की। कांग्रेस पेंशन के अपने वादे से खुद ही परेशान हो गई। इसके चलते लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में इस वादे को शामिल ही नहीं किया गया। कांग्रेस सिर्फ वोट हासिल करने के लिए घोषणा करती है। जनता को उसके फैसलों पर भरोसा नहीं है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने मिस इंडिया लिस्ट में दलित, आदिवासी और ओबीसी नहीं वाले राहुल गांधी के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओबीसी के बारे में बात करते हैं, यह अच्छा है। यह उनका अधिकार भी है, लेकिन वह बहस को इतना नीचे ले जाएंगे? जातिगत जनगणना गंभीर मुद्दा है.

आजाद पार्टी ने 13, आप ने सात उम्मीदवारों की सूची की जारी

जम्मू। जम्मू और कश्मीर पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में आजाद के करीबी गुलाम मोहम्मद सरूरी का नाम नहीं है। वह इंद्रवल से विधायक रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सात उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपोरा से मुद्दसीर हुसैन, देवसर से शेख फिदा हुसैन, दौरू से मोहसिन शाफकत मीर, डोडा से मेहराज दीन मलिक, डोडा वेस्ट से यासिर सफी मट्टो और बनीहाल से मुद्दसीर अजमत मीर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम प्रमुख है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में आजाद के करीबी गुलाम मोहम्मद सरूरी का नाम नहीं है। वह इंद्रवल से विधायक रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इंद्रवल में उन्होंने रविवार को बैठक कर आम कार्यकर्ताओं की राय ली कि उन्हें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए या नहीं। विधानसभा के दूरदराज के क्षेत्रों से आए उनके समर्थकों ने एक स्वर में समर्थन देते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा।

चुनावों से पहले कांग्रेस ने ऐसे घेरा भाजपा को

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को वास्तविक घरेलू आय में लगातार हो रही गिरावट पर घेरना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में देश में वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट हो रही है। उनका कहना है कि धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी और आय में जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। जयराम रमेश कहते हैं कि अपंजीकृत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक के KLEMS डाटा और घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ने देश में रोजमर्रा का काम करने वाले समुदाय के लोगों के बीच वित्तीय संकट की बात कही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़ों सहित डाटा के कई स्रोतों ने इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी दिखाए हैं कि श्रमिकों की खरीदारी करने की क्षमता भी बीते 10 साल पहले की तुलना में कम हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस तरीके के बदले हालतों में अब केंद्र सरकार को जवाब तो देना ही होगा। जयराम रमेश कहते हैं कि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में 2019 से 2024 के बीच में गिरावट दर्ज हुई है। यह आंकड़े केंद्र सरकार के श्रम ब्यूरो के वेतन दर सूचकांक से ही निकले हैं।

जातिगत जनगणना का चिराग ने किया समर्थन

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की रविवार को रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस बात की घोषणा की। पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि चिराग को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने के निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर चिराग ने कहा, आज रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देशभर से हमारे कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पासवान ने आगे कहा कि बैठक में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गयी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि झारखंड में उनकी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन की अपनी साझेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ या अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। पासवान ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा, मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा है।

यूपीएस देने के बाद भी कर्मचारी संगठनों की सरकार से नाराजगी बरकरार

कीर्तिवर्धन मिश्र

पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम की योजना 2004 से ही लागू हुई थी और तभी से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी सरकारी कर्मचारियों ने कई बार बड़े धरना-प्रदर्शन कर सरकार पर पुरानी पेंशन देने का दबाव बनाया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में झटका खाने के कुछ दिनों बाद ही सरकार ने नई और पुरानी पेंशन के बीच यूपीएस लागू करने का वादा कर दिया है। इससे कर्मचारियों की नाराजगी कुछ हद तक कम होने की बात सामने आ रही है, हालांकि, पुरानी पेंशन की तुलना में नई पेंशन में कम लाभ होने के कारण इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में कर्मचारी संगठन इसका तगड़ा विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी सरकार ने दो कदम आगे बढ़ने का निर्णय किया अवश्य है, लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानी कम करने वाली नहीं दिखती।

दरअसल, माना जा रहा है कि सरकार ने एनपीएस से होने वाले नुकसान का अनुमान लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही लगा लिया था, लेकिन यह नुकसान कितना व्यापक हो सकता है, इसका उसे अनुमान नहीं था। इस गफलत के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि इसके पहले कई कठोर निर्णय के बाद भी उसे जनता का साथ मिलता रहा और उसने बड़ी जीत हासिल करने में सफलता पाई थी।

किसान आंदोलन ऐसे मामलों में सबसे ऊपर रखा जा सकता है। तीन विवादित कृषि कानूनों के विरोध में जहां किसानों ने सड़कों पर जाम लगा रखा था, वहीं सरकार इसे पीछे न लेने पर अड़ी हुई थी। इसी दौर में सरकार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का सामना करना पड़ा। किसान संगठनों ने दावा किया था कि सरकार को इन आंदोलनों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार को किसान आंदोलनों के कारण कोई बड़ा

नुकसान नहीं हुआ, उलटे उसने पंजाब छोड़कर सभी चार राज्यों में सरकार बनाने में सफलता पाई थी।

राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडेय का कहना है कि इस तरह के कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद भी राजनीतिक सफलता पाने से कहीं न कहीं सरकार के मन में यह भाव पैदा हो गया कि जनता का उसे व्यापक स्तर पर समर्थन हासिल है, इसलिए वह कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन ऐसा सोचते समय सरकार ने यह नहीं सोचा कि लोगों के बीच जनमत का निर्माण करने में सरकारी कर्मचारी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे चुनाव संचालन की प्रक्रिया को भी निचले स्तर पर प्रभावित करते हैं। संभवत: यही कारण है कि जब सरकारी कर्मचारियों ने सरकार का साथ नहीं दिया, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।

चुनाव के कारण हुआ है यह निर्णय

वहीं, कुमार राकेश का मानना है कि सरकार अभी से 2029 की तैयारी में जुट गई है। सरकार के सामने हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के चुनाव हैं। इसके बाद उसे महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों का सामना करना है। अभी तक के जो समीकरण सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें भाजपा को हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली में बेहद कड़ी चुनौती मिलने वाली है।

यदि इन राज्यों में भाजपा को करारी मात मिलती है तो इससे विपक्ष के हौसले बुलंद होंगे, जो उसे 2029 की लड़ाई में कमजोर करेंगे। जबकि यदि सरकार की यूपीएस स्कीम से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हो जाते हैं, तो इससे वह न केवल चुनावी दौड़ में वापस लौट सकती है, बल्कि कुछ जगहों पर मजबूत लड़ाई में वापसी भी कर सकती है। संभवत: यही कारण है कि सरकार ने इस समय यूपीएस लाने का निर्णय किया है।

लेकिन विरोध बरकरार

यूपीएस देने के बाद भी कर्मचारी संगठनों की सरकार से नाराजगी बरकरार है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन इप्सेफ के राष्ट्रीय सह महासचिव डॉ. अतुल मिश्रा ने अमर उजाला से कहा कि नई पेंशन देने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से ही दस फ़ीसदी अंशदान लेने का निर्णय कर लिया है। ऐसे में यह सरकारी कर्मचारियों के ऊपर बड़ा बोझ है।

उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते पहले ही वेतन बहुत कम है, यदि उसमें से दस फ़ीसदी पेंशन के नाम पर कम कर दिया जाएगा, तो इससे कर्मचारियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि उनके संगठन ने सरकार के इस कदम का विरोध करने का निर्णय किया है। वे सरकार के सक्षम लोगों से मिलकर यह मांग उठाना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार ने मांगें नहीं मानी, तो वे सरकार का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। यानी यूपीएस की घोषणा करने के बाद भी सरकार की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं।

मुख्य न्यायाधिपति ने जशपुर न्यायालय का किया निरीक्षण

जशपुर। जशपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने जिला जशपुर के तालुका न्यायालय, व्यवहार न्यायालय बगीचा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर का निरीक्षण किया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हुए। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा व्यवहार न्यायालय बगीचा के निरीक्षण उपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पहुंचने पर मुख्य न्यायाधिपति का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर के न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने स्वागत किया।

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर के कोर्ट के संचालन के लिए बने विभिन्न अनुभाग अभिलेखागार, कंप्यूटर सर्वर रूम, फर्स्ट एड क्लीनिक, मालखाना, बच्चों के लिए बने किलकारी कक्ष, कुटुम्ब न्यायालय, अधिवक्ता कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया और अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों से चर्चा के दौरान कहा कि मैं आज लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय कर बिलासपुर से आप लोगों से मिलने और आप लोगों की समस्याओं से अवगत होने के लिए आया हूं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में बने न्यायालय में जाकर वे वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कमी हो तो सुधार किया जा सके और न्याय व्यवस्था आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने

किलकारी कक्ष के निरीक्षण के दौरान वहां पर मौजूद कक्षा पहली में पढने वाले मयंक यादव से बात की और उसे उपहार प्रदान करते हुए उक्त बालक के साथ फोटो भी लिया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री हिरेन्द्र सिंह टेकाम भी मुख्य न्यायाधिपति के साथ मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने अधिवक्ताओं से चर्चा के दौरान कहा की वे यहां पहली बार आ रहे हैं। जशपुर जिले का नैसर्गिक सौंदर्य सहज ही आकर्षित करने वाला है, जशपुर जिला छत्तीसगढ का कश्मीर है। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने कहा कि न्याय की व्यवस्था को सुदूर अंचल तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को डिजिटल किया गया है ताकि किसी भी स्थान से अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपने प्रकरण में जिरह कर सकें। अन्य सुविधा के लिए मोबाईल एप भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से सुदूर अंचल के निवासी एवं गरीब पक्षकार भी लाभ प्राप्त कर समय एवं पैसे का बचत कर सके।

मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने जशपुर जिले के व्यवहार न्यायालय कुनकुरी के न्यायालय एवं सभी अनुभाग का निरीक्षण भी किया एवं अधिवक्ताओं से सौजन्य मुलाकात किया। मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उक्त न्यायालयों के रख-रखाव एवं व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त किया एवं भविष्य में अधिक बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम सुधार हेतु प्रोत्साहित किया।

निरीक्षण के दौरान उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल श्री बलराम प्रसाद वर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार सह पीपीएस श्री एम.वी.एल.एन. सुब्रहमन्यम, प्रोटोकॉल ऑफिसर श्री आर.एस. नेगी एवं पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह एवं पुलिस के अन्य अधिकारी, कमर्चारी, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री भागवत नारायण सिंह सहित अन्य अधिवक्तागण तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर, व्यवहार न्यायालय कुनकुरी एवं व्यवहार न्यायालय बगीचा के न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

बिलासपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन स्ट्रीट, एटीएम लूटने का प्लान हुआ डिकोड

बिलासपुर। गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए बिलासपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट चलाया है। ऑपरेशन स्ट्रीट के तहत पुलिस ने शहर के जरहाभाठा जतिया तालाब के पास से 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पकड़े गए गुंडों के पास से पुलिस ने पिस्टल दो मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 6 देशी कट्टे, तलवार और चाकू बर्मद किया है। पकड़े गए लोगों के पास से कार सहित दस मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि मिनी बस्ती जतदिया तालाब के आस पास बड़ी संख्या में अपराधी मौजूद हैं। सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी शुरु की। पुलिस की कार्रवाई में जतिया तालाब के पास से 11 नामी बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी बदमाश

आदतन अपराधी हैं। पकड़े गए बदमाश एटीएम लूट की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक, रजनेश सिंह ने कहा पुलिस के मिली सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई में एसीयू टीम और सिविल लाइन पुलिस की टीम शामिल रही। संयुक्त टीम ने मिलकर जरहाभाठा जतिया तालाब के पास रेड किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरु की तो कुछ बदमाश भागने लगे। पुलिस ने सभी को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुआ है। पकड़ा गए लोगों ने बताया कि वो हथियार के दम पर एटीएम लूट का प्लान बना रहे थे।

एसपी रजनेश सिंह ने की इनाम देने की घोषणा

बिलासपुर एसपी ने पुलिस की सफल कार्रवाई पर खुश होते हुए टीम को इनाम देने की घोषणा की है। एसपी ने कहा है कि शह को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई पुराने मामलों में भी इनकी सहभागिता होने के सबूत मिल सकते हैं।

अनुकम्पा नियुक्ति की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज

- कहा- आर्थिक संकट या गरीबी तय बुनियादी मापदंड

बिलासपुर। अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में लगाई गई तीन अलग-अलग याचिकाओं को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिवार के सामने आने वाला आर्थिक संकट या गरीबी अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए तय बुनियादी मापदंड हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता।

केस 1- रतनपुर में रहने वाले रामाधार तिवारी की पत्नी ने पति की मौत के बाद छोटे बेटे को अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग करते हुए याचिका लगाई गई। जिसमें कहा गया, कि उनके पति पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। 20 अगस्त 2007 को सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने छोटे बेटे दीनानाथ तिवारी को अनुकंपा

नियुक्ति के लिए अक्टूबर और दिसंबर 2007 में बिलासपुर एसपी को आवेदन दिया।

अगस्त 2012 में आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके लिए आधार बताया गया कि दीनानाथ के बड़े भाई केदारनाथ शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर कार्यरत हैं। इस फैसले को चुनौती देते हुए 2014 में याचिका लगाई। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

केस 2- इसी तरह बैकुंठपुर के रहने वाले यश मिश्रा को पिता की मौत के बाद अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी। उनकी मां सुनीता मिश्रा व्याख्याता थीं। वर्ष 2018 में मां के सरकारी नौकरी में रहने के आधार पर विभाग ने उन्हें सेवामुक्त कर दिया। जिसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई। यश ने अपने आवेदन में बताया था कि पिता की मौत के दौरान वह भिलाई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पिता को ब्रेन कैंसर था। उनके इलाज में पूरी रकम खर्च हो गई। पिता की मौत के बाद पढ़ाई छोड़कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी।

केस 3- कांकेर के रहने वाली सुमन के पिता राममूर्ति शर्मा ग्रामीण स्वास्थ्य संगठक के पद पर कार्यरत थे। जून 2019 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सुमन ने जुलाई 2019 में राजनांदगाव के सीएमएचओ दफ्तर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। उनके भाई रमन शर्मा के कांकेर के गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 बॉयोलॉजी के पद कार्यरत होने के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसे लेकर होने कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू को जान से मारने की कोशिश

मां और बेटा गिरफ्तार, भेजा गया जेल

कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने दहेज लोभी मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मिलकर हत्या की कोशिश किया है। मामला पांडातराई थाना क्षेत्र का है। एडिशनल एसपी पुष्पेन्द्र बघेल ने बताया कि प्रार्थीया शकुंतला पाली पति रामानुज पाली उम्र 25 निवासी ग्राम सोढा थाना पांडातराई ने 23 अगस्त को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपने आवेदन में बताया कि इसके पति रामानुज पाली व सास सुखबती पाली द्वारा इसे पसंद नहीं करना, दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

घटना तारीख 5 अगस्त दोपहर 12 खेत में काम करने के लिए गई थी। तब इसके पीछे-पीछे पति व सास भी चले गए। रस्सी को गला में फंसाकर हत्या करने के नियत से कंसकर दोनो तरफ से खिंचे, जिससे बेहोश हो गई। तब इसे मरा हुआ समझकर खेत में ही छोड़कर वहां से चले गए। आसपास में काम कर रहे लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 5 दिन बाद अस्पताल में होश आई।

घटना की बात अपने माता-पिता व गांव के सरपंच को बताई। इस पर पुलिस ने आरोपी पति रामानुज पाली व सास सुखबती पाली के खिलाफ धारा 109, 85, 3(5) बीएनएस दर्ज कर जांच शुरू किया। जांच के दौरान पति व सास को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी रामानुज पाली से मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त रस्सी को जब्त किया गया। दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से जेल दाखिल कर दिया गया है।

साइकिल सवार को कुचलते हुए पिकअप वाहन पलटा

हादसे में 18 लोग घायल, चार की हालत गंभीर

जगदलपुर। कोंडागाँव जिले के अनंतपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार पिकअप चालक ने सायकिल सवार को ठोकर मार दिया, इस घटना में साइकिल सवार की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वही घटना के बाद पिकअप चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पिकअप पलट गया, इस घटना में पिकअप में सवार सभी घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों को गंभीर चोट आने के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए कोंडागाँव जिला अस्पताल भेजा गया, घायलों में ज्यादातर महिलाएं शामिल होने की बात भी सामने आई।

मामले कि जानकारी देते हुए अनंतपुर थाना प्रभारी अखिलेश धीवर ने बताया कि शनिवार की रात को कोंडागांव जिला क्षेत्र के हीरापुर एरला मार्ग पर ग्राम सिवनी में यात्रियों से भरी पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को कुचल दिया, इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अनियंत्रित पिकअप पलट गई, जिसमें पिकअप सवार 18 लोग घायल हुए हैं, घायलों में चार लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अनंतपुर थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, पुलिस के द्वारा घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनंतपुर में प्राथमिक उपचार कराया गया है, उसके बर्फ तीन एंबुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल कोंडागांव रेफर कराया गया है, पिकअप वाहन पर सवार सभी लोग ग्राम मिरमिंडा में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होकर उमरगांव, चिपावंड वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भारत स्काउट्स गाइड्स के शिविर में कर्म के साथ धर्म भी

बिलासपुर। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य पुरस्कार जांच शिविर का आयोजन बिलासपुर में किया गया है। इसमे बिलासपुर और सरगुजा संभाग के 168 गाइड, प्रभारी और गाइड कैप्टन शिविर में भाग लें रहे हैं। गुरुवार को शिविर में राज्य मुख्य आयुक्त डा. सोमनाथ यादव पहुंचे थे तब गाइड कैप्टन द्वारा कमर्छठ पर बच्चों के लिए पूजा, व्रत रखने की चिंता जाहिर की। डा. सोमनाथ यादव ने तुरंत शिविर स्थल पर ही कमर्छठ पूजा हेतु सारी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। शनिवार को शिविर स्थल पर पूजा-अर्चना हुई उसके बाद सभी महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुखद संयोग ये रहा कि सम्पूर्ण कार्य यहां तक पूजा कार्य भी गाइडर द्वारा किया गया। कर्तव्य के साथ धर्म कार्य करना स्काउटिंग की विशेषता है जिसे गाइड विभाग ने आज कर दिखाया।

अब वृद्धा ध्वजा बाई को पैसे मांगने की नहीं पड़ती जरूरत

कोरबा। पाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम हरनमुड़ी की 70 वर्षीय वृद्धा ध्वजा बाई को कुछ माह पहले तक अपनी छोटी-छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों से पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ती थी। कई बार कुछ रूपए के लिए उन्हें लंबा इंतजार भी करना पड़ता था। अब जबकि महतारी वंदन योजना से हर महीने खाते में 01 हजार रूपए समय पर मिल जाते हैं तो वृद्धा ध्वजा बाई को किसी के आगे रूपए के लिए हाथ फेलाने जैसी नौबत नहीं आती है। ग्राम हरनमुड़ी की वृद्धा ध्वजा बाई ने बताया कि उम्र के साथ ही उन्हें कुछ भी काम करने में परेशानी है वह किसी तरह छोटे-मोटे घरेलू काम कर लेती है। उन्होंने बताया कि विगत माह महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का आहरण किया है। इस राशि का उपयोग अपने उपचार और बीमारी के दौरान दवा, फल आदि में किया है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद हम जैसी वृद्ध महिलाओं के लिए यह वरदान साबित हो रही है। हर महीने खाते में 01 हजार की राशि प्राप्त हो जाती है।

नहरिया बाबा मंदिर में ढाई लाख से अधिक की चोरी

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध नहरिया बाबा मंदिर में चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मंदिर से करीब ढाई लाख रुपये की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में तीन चोर नजर आ रहे हैं। एसपी विवेक शुक्ला ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। घटना नैला चौकी उप थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी अनुसार, शनिवार की देर रात प्रसिद्ध नहरिया बाबा मंदिर में चोरी की हुई है। तीन चोरों मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। जिसमें चोर रैनकोट और नकाब पहने हुए है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच में जुटी हुई है। एसपी विवेक शुक्ला भी मौके पर पहुंचे हुए थे। नहरिया बाबा मंदिर में इससे पहले भी चोरी हो चुकी है। चोरों का पता नहीं चल सका। मंदिर से पुजारियों के रखे 35 हजार रुपये नगदी रकम और तीन दान पेटी लगभग ढाई लाख रुपये की चोरी की गई है।

दूर हुआ पहाड़ी कोरवा दुखुराम का दुख

कोरबा। पहाड़ी कोरवा युवक दुखुराम की अब दिनचर्या ही बदल गई है। राज्य शासन से नौकरी मिलने के पश्चात एक नया सपना सजने लगा है। कुछ साल पहले रोजगार नहीं होने से पूरा दिन जंगलों में चार, तेंदू, महुआ आदि फल-फूल एकत्रित करने में समय गुजर जाता था। भूख मिटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ऐसे में एक सामान्य जनजीवन व्यतीत करना एक कल्पना ही थी। लेकिन यह कल्पना एक दिन हकीकत में बदल जायेगी यह पहाड़ी कोरवा दुखुराम ने भी नहीं सोचा था। राज्य शासन की पहल ने आज उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि अब वह इतिहास में जाना नही चाहता। सरकारी नौकरी के बाद अपनी दुखों से दूर हुए पहाड़ी कोरवा दुखुराम अपना भविष्य सुधारने के साथ बच्चों का भविष्य बनाने की सोचने लगा है। नौकरी से न सिर्फ दुखुराम का जीवन बदला है, उनकी पत्नी सहित परिवार को भी जीवन का सुख मिलने लगा है। वर्तमान में कोरबा जिले के ग्राम पेण्ड्रीडीह में रहने वाला दुखुराम को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी प्रदान की गई है।

खूंखार तेंदुए ने घर में घुसकर तीन बकरों पर किया हमला

कांकेर। कांकेर जिला मुख्यालय से लगे गोविंदपुर गांव में खूंखार तेंदुआ आ धमका है। देर रात तेंदुआ एक घर में घुसा और तीन बकरों पर हमला कर दिया है, जिससे दो बकरों की मौत हो गई है। वहीं एक बकरे को मारकर अपने साथ जंगल की ओर ले गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार गोविंदपुर निवासी मनोज पाल के घर तेंदुए ने हमला किया है। तेंदुए ने दो छोटे बकरी के बच्चे को मार दिया और एक बकरा को जंगल उठा ले गया। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग को दी है, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी गोविंदपुर में तेंदुए ने मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है। इन दिनों गोविंदपुर में जंगली जानवरों का खतरा हो गया है।

गौरेला के बोईरडांड गांव में गायब हो गई नाली को खोजेंगे अफसर

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला जनपद पंचायत में एक बार फिर भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है। दरअसल साल 2018 और 19 के बीच 208 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया गया। नाली का निर्माण मनरेगा कार्य के तहत कराया गया। नाली निर्माण की जिम्मेदारी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत बेलपत के जिम्मे रही। नाली निर्माण के दो सालों बाद फिर से इसी नाली के निर्माण की बात सामने आई है। गांव वालों का आरोप है कि इसी नाली के 20.60 मीटर के हिस्से को फिर बनाकर दिखाया और उसके पैसे ले लिए गए। फर्जी भुगतान का आरोप लगा है।

नाली निर्माण का काम दिखाकर कहा जा रहा है कि पैसों का भुगतान भी करा लिया गया। जबकी हकीकत में मौके पर 20.60 मीटर लंबी नाली गायब है। शिकायत मिलने पर अब अधिकारी जरुर

ये कह रहे हैं कि अगर कहीं घोटाल हुआ है तो जांच की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी अधिकारियों ने कही है।

पंच अहिल्या बाई ने कहा नाली बन रही थी। सब तो नजर के सामने है। सब लोग देख रहे हैं। इंजीनियर तो कभी काम को देखने तक नहीं आया।

ग्रामीण सुखदेव सिंह ने कहा नाली तो नहीं बनी खुदाई जरुर हुई तो आगे तक। दोबारा काम लगा नहीं नाली के लिए। नाली को बनते तो मैंने देखा ही नहीं।

बेलपत ग्राम पंचायत के बोईरडांड मोहल्ले का ये पूरा मामला है। आरोप है कि मनरेगा के तहत बनाई गई 228.6 मीटर नाली से 20.60 मीटर नाली चोरी हो गई। गांव वालों का कहना है कि 20।60 मीटर नाली मौके पर है ही नही। साल 2018-19 में 208.00 मीटर नाली का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य-एजेंसी ग्राम पंचायत बेलपत द्वारा 07-06-2019 तक बना ली गई थी। संबंधित कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका में दर्ज भी किया गया।

विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रोशन सराफ के द्वारा सुनील ट्रेडर्स को एफटीओ के माध्यम से दिनांक 22/02/2020 को भुगतान भी कर दिया गया। माप पुस्तिका में कार्य पूरा होने के लगभग 2 साल बाद, ठीक उसी जगह पर उसी नाली के आगे 20।60 मीटर की नाली निर्माण फर्जी तरीके से कागजों पर बनना दिखाया गया। गांव वालों ने जब खुद नाली की नापी की तो नाली की लंबाई 208 मीटर ही निकली। गांव वालों का आरोप है कि 20.60 मीटर नाली मौके से गायब है।

ग्रामीण नरेंद्र सिंह ने कहा नाली तो यहां 208 मीटर ही निकली। खुदाई जरुर आगे साइड हुई थी लेकिन काम हुआ नहीं। आगे दोबारा नाली बनी नहीं। इंजीनियर को हमने कभी नहीं देखा।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौशल तेंदुलकर ने कहा खबर के माध्यम से ये पता चला है कि नाली में भ्रष्टाचार के सामने सामने आए हैं। एक जांच कमेटी जिला स्तर पर बनाए हैं। जो भी गड़बड़ियां सामने आएगी उसपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा है कि शिकायत तो सामने आई है उसके मुताबिक जांच दल गठित की गई है। जल्द ही जांच दल मौके पर जाकर इस बात की तस्दीक करेगा किया सच है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भरोसा दिया है कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ओड़िशा के गांजा तस्कर को 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना

कबीरधाम। कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ओड़िशा के एक गांजा तस्कर को 20 साल की जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मिली जानकारी अनुसार यह मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है।

यहां की पुलिस ने 24 दिसंबर 2020 को 6 क्विंटल 75 किलो गांजा के साथ आरोपी प्रमोद घोष पिता पुन्नाचंद्र घोष उम्र 22 निवासी मदरोकोट थाना कोड़ला जिला गंजम (ओड़िशा) को गिरफ्तार किया था। आरोपी ट्रक क्रमांक एपी 07 टीडब्ल्यू-0457 से गांजा को ले जा रहा था। पुलिस ने इसे थाना के सामने रुकवा कर चेकिंग किया। इस दौरान ट्रक में मोडिफाई चैंबर बनाकर गांजा को रखा गया था।

उक्त गांजा को ओड़िशा राज्य से लाकर कबीरधाम होते आगरा के विभिन्न स्थान में खपाने की तैयारी थी। इससे पहले चिल्फी में आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।कोर्ट में साढ़े तीन साल चली सुनवाई बाद आरोपी को 20 साल की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

संक्षिप्त समाचार

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर विस अध्यक्ष ने दिया प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश वासियां को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। अपने संदेश में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि-भगवान श्रीकृष्ण का जीवन फल की चाह से मुक्त सतत् कर्मवाद के सिद्धांत का विराट एवं साक्षात् स्वरूप है। उन्होंने कहा कि-भगवान श्रीकृष्ण ने आतंक, निराशा, शोषण, पराधीनता और भाग्यवाद जैसी कुरीतियों से लडने् के लिए जन-जन के अंदर प्रतिरोध मुखर करने की शक्ति तथा साहस का संचार किया। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि-भगवान श्रीकृष्ण जीवन को उत्साह से जीने की सीख देते है, और सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित भी करते हैं। डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर आह्वान किया कि श्रीकृष्ण के जीवन से कर्म की प्रधानता की शिक्षा ग्रहण करते हुए उसे अपने कार्य, व्यवहार एवं आचरण में आत्मसात् करना चाहिए।

श्री जैतुसाव मठ में आज मनायी जायेगी कृष्ण जन्माष्टमी

रायपुर। श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी जैतूसाव मठ न्यास समिति के सचिव श्री महेन्द्र अग्रवाल एवं न्यासी अजय तिवारी ने एक संयुक्त वित्रप्ति में जानकारी दी है कि प्रतिवर्षनुसार श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव सोमवार 26 अगस्त को मनायी जायेगी। इस दिन रात्रि में ठीक 12 बजे श्री कृष्णा जी के जन्म के समय महाआरती की जावेगी इसके लिए मठ पारंपरिक रूप से सजधज कर तैयार है तथा मंदिर में स्थापित सभी विग्रहों का दुग्धाभिषेक कर नवीन वस्त्र अलंकार से सुसज्जित कर महाआरती की जावेगी। इस कार्यक्रम को देखने सैकड़ों श्रद्धालु आते है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रात्रि 8 बजे से श्री लल्लू महराज एवं उनकी पार्टी द्वारा भजन कीर्तन एवं राधा कृष्ण की झांकी होगी जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा । दूसरे दिन 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1 बजे श्री राजभोग आरती होगा एवं प्रसाद वितरण संध्या 5 बजे से होगा।

भाजपा सदस्यता अभियान का वार रूम उद्घाटित

रायपुर। भाजपा सदस्यता अभियान वार रूम

का उद्घाटन आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में किया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव, केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू, मुरलीधर मोहोल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे, मंत्री केदार कश्यप, सदस्यता अभियान के प्रभारी अनुराग सिंहदेव, विधायक गुरु खुशवंत, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सव्वनी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा,पूर्व विधायक नारायण चंदेल, रजनीश सिंह, नवीन मार्कण्डेय सहित वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे।

राज्यपाल रमेन डेका ने किए महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायपुर के

गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ के समस्त वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना कीं। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

एक दिवसीय कार्यशाला दिल्ली में, शामिल हुई छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष शालिनी

रायपुर। नई दिल्ली विस्तार भवन में सदस्यता

अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा विनोद तावडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा रेखा वर्मा (महिला मोर्चा सदस्यता अभियान प्रभारी), राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वनाथी श्रीनिवासन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विभिन्न जानकारी सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में दी गई। 1 सितंबर से होने जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यशाला में भारत के लगभग 28 राज्यों से प्रतिनिधित्व शामिल हुए जिसमें छत्तीसगढ़ से बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष ममता साहू उपस्थित रहे। 28 अगस्त को संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, जिला अध्यक्ष एवं जिला के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

रायपुर में एनसीबी के कार्यालय का गृह मंत्री शाह ने किया उद्घाटन

कहा- नशा मुक्त भारत, समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण

रायपुर। नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। एक प्रकार से देखे तो नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समस्या है। मगर भारत में सबसे ज्यादा जागरूकता रखने की जरूरत है। अगर यह लड़ाई हम शिद्दत और रणनीति के साथ लड़े तो यह लड़ाई हम जीत सकते हैं। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नया रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया के कई देश यह लड़ाई हार चुके हैं। भारत में नारकोटिक्स का दूषण नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। नारकोटिक के अवैध व्यापार से जो धन अर्जित होता है, उस धन का उपयोग टेररिज्म, नक्सलिज्म और भारत के अर्थतंत्र को निर्बल करने का काम में भी आता है। नारकोटिक्स का एक ओर हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का लक्ष्य है और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को अवैध व्यापार के कमाए गए पैसे से प्रभावित करना भी लक्ष्य है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जीरो टॉलरेंस की वृद्धि के साथ देश को नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, उसको साकार करें।

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है। और धीरे-धीरे यह संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है।

एनसीबी ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 5000 वर्ग फुट में फैला हुआ यह कार्यालय नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा हमें भूमि और बाकी सारी सुविधाएं राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे अंचल में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमित शाह ने बताया कि हमने लक्ष्य रखा है कि देश के हर एक राज्य में नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस खोला जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का मंत्रालय प्रयास करेगा।

ड्रग ट्रैफिकिंग का बदल रहा ट्रेंड

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और उसकी सबसे ज्यादा कीमत भी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सेडेटिव के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ सात राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बंगाल की खाड़ी के नजदीक भी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्टल कनेक्टिविटी भी ड्रग का एक रूट तैयार करती है और गांजा की तस्करी आंध्र और ओडिशा सीमा से होती है।

छत्तीसगढ़ में गांजे का नशे में उपयोग राष्ट्रीय औसत से दोगुना

छत्तीसगढ़ में गांजा के नशे का उपयोग करता 4.98 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 2.83 से बहुत अधिक है। वह हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी लोगों से आग्रह है कि इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से देखें।

साइंटिफिक में टॉप टू बॉटम और बॉटम तो टॉप एप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि एक छोटी सी दुकान पर अगर नशे की पुड़िया मिलती है तो वह देश में कहां से आई, कहां पर बनी तक का इन्वेस्टिगेशन करके हमें नेटवर्क का धवस्त करने का काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स का केस कोई नारकोटिक्स का केस नहीं हो सकता है पूरे तंत्र को उसकी पूरी बैकग्राउंड को ध्वस्त करने के दिशा में काम करना होगा।

छत्तीसगढ़ में 7 पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। पुनर्वास की अपग्रेडेशन की चिंता करनी चाहिए। 14 नशा मुक्ति केंद्र राज्य सरकार भी चल रही है। जो ड्रग का व्यापार करता है वह गुनहगार है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का उपयोग हो रहा है। कई जगह पर ड्रोन के द्वारा डिलीवरी के किस्से सामने आए हैं।

गृह मंत्री ने पेश किये कार्रवाई के आंकड़े

मोदी सरकार बनने के बाद ठ्ष्क्ष् का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हैं। 2004 से 14 तक 1250 केस रजिस्टर्ड हुए थे। अब 4150 केस रजिस्टर्ड हुए। केस में 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले अरेस्टिंग 1360 था अब 6300 हुआ है। पहले 1.52 लाख किलो नारकोटिक्स पकड़ा गया था अब 5 लाख 43 हजार किलो पकड़ा गया। पहले 5900 करोड़ अब 22000 करोड़ के ड्रग सीज किये। 10 साल में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचने में सफल हुए है। अभी भी काफी काम बाकी है।

कुतुब मीनार-ताजमहल के स्थान पर पहले था मंदिर: विष्णु

वरिष्ठ अधिवक्ता ने हिंदू धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना पर दिया जोर

- **सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी मंदिरों को स्वतंत्र करने की मांग**

रायपुर। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, और ज्ञानवापी मंदिर के मामलों में हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने देश में सनातन बोर्ड के गठन की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों जैसे कुतुब मीनार और ताजमहल की भूमि पर पहले मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिदों में बदल दिया गया। इस तरह के मुद्दों पर उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की बात की है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ये मंदिर राष्ट्रीय गौरव का

प्रतीक हैं और उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस लाने की जरूरत है। राजधानी रायपुर में स्व.कुंदनलाल जैन की समृति में आयोजित राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे जैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि 22 जनवरी जैसा महत्वपूर्ण दिन फिर से काशी और मथुरा में वापस आएगा, जो कि हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कर सकती है और इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। विष्णु शंकर जैन का मानना है कि ऐसे बोर्ड का गठन सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा और उसके पुनर्जागरण पर जोर दिया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह समय है कि देश अपने गौरवशाली इतिहास और धार्मिक धरोहरों को पुनर्जीवित करे और इसे अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करे।

भाजपा ने सदस्यता अभियान के मण्डल प्रभारी व संयोजक नियुक्त किए

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी पहली सितम्बर से आरंभ हो रहे सदस्यता अभियान के लिये जिले के सभी 11 मण्डलों के प्रभारी और मण्डल वार संयोजक व सदस्यों की नियुक्ति भाजपा जिला अध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी ने की है। जिसमें योगेन्द्र पाण्डेय तोकापाल व करपावण्ड मण्डल के होंगे।

ऐसे ही रामाश्रय सिंह को नगरनार व जगदलपुर मण्डल, रजनीश पाणिग्रही नानगूर व दरभा, नरसिंह राव लोहण्डीगुड़ा व बास्तानार, व्हीएस राजपूत भानपुरी व बस्तर मण्डल एवं स्नेहलता बैस को बकावण्ड मण्डल का सदस्यता अभियान प्रभारी बनाया गया है। भाजपा सदस्यता अभियान को गति देने जिले के सभी मण्डल में संयोजक सहित चार सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। जिसके तहत बस्तर मण्डल में संयोजक नरेंद्र जोशी व सदस्य गणेश बघेल, चमरू राम, चमेली साहू, मानसाय बघेल, नगरनार मण्डल में संयोजक रघु सेठियाव सदस्य महादेव बघेल, मोहन सेठिया, चमेली जिराम, फूल सिंह नायर, करपावण्ड मण्डल में संयोजक पुलकेश्वर पाण्डेय व सदस्य जेपी बैद्य, विषम ठाकुर, तरूण पाण्डेय, ललिता कश्यप, तोकापाल मण्डल में संयोजक सोमारूराम कश्यप व सदस्य परदेशी कश्यप, रैतुराम बघेल, शांति नाग, रामबती भण्डारी, बास्तानार मण्डल में संयोजक संतोष सिंह ठाकुर व सदस्य सुनील कुर्राम, कमल सिंह ठाकुर, प्रिया मुचाकी, सोहन पोशाक, नानगूर मण्डल में संयोजक नीलाम्बर सेठियाव सदस्य धरमु मण्डावी, कमल कुमारी सेठिया, लखमु बघेल, राजू पोयाम, बकावण्ड मण्डल में संयोजक पुरुषोत्तम जोशी व सदस्य दामोदर बघेल, धनमती बिसाई आदि बनाये गये हैं।

आतंक प्रभावित बीजापुर जिले के पालनार कैम्प के आसपास के 31 युवाओं ने शाह से की मुलाकात

कई युवाओं ने पहली बार देखी राजधानी रायपुर

रायपुर। माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के पालनार कैम्प के आस-पास के 5 गांव के 31 युवाओं ने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से नवा रायपुर में मुलाकात की। इनमें से कई युवा पहली बार बीजापुर से निकलकर राजधानी रायपुर आये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने इन बच्चों से हाल-चाल पूछा और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इन बच्चों ने राजधानी रायपुर के भ्रमण के दौरान पुरखौती मुक्तागन, महानदी भवन मंत्रालय, मीवान स्टील प्लांट, मैग्नेटो मॉल, अंतर्राष्टीय क्रिकेट स्टेडियम, पुरखौती मुक्तांगन, रेलवे स्टेशन और मैग्नेटो माल का भ्रमण किये। 23 अगस्त की रात से यह युवा रायपुर पहुँचे हैं। युवा कल गंगरेल बांध घूमते हुए वापस बीजापुर लौट जाएँगे।

गौरतलब है कि पालनार सुरक्षा कैम्प के आस-पास के इन बच्चों के गांवों में नियद नेल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली पानी राशन, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी सहित सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा कैम्प के पांच किलोमीटर की परीधि के गांवों में नियद नेल्लानार योजना संचालित की जा रही है। बीजापुर जिले के सुरक्षा कैम्पों के पास के 33 गांवों में नियद नेल्लानार योजना संचालित की जा रही है। बीजापुर जिला प्रशासन की पहल पर पालनार कैम्प के पास के इन गांवों के बच्चों को राजधानी रायपुर में औद्योगिक विकास सहित रोजगार के क्षेत्र में नए नए अवसर एवं विकास की सभी गतिविधियों से परिचित कराया गया है। इससे इन युवाओं में नए उत्साह का संचार दिख रहा है। ये युवा अब रोजगार मूलक गतिविधियों से जुड़कर अपना नया और सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं।

विशाखा राय के सिर पर सजा फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 का ताज

राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी राज्य का प्रतिनिधित्व

रायपुर। फेमिना मिस इंडिया 2024 के 60वें संस्करण में विशाखा राय ने मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब जीता है। मुंबई के टाइम्स टावर में आयोजित एक शानदार समारोह के बाद 21 वर्षीय राय विशाखा के सर पर ताज सजाया गया, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती साल छत्तीसगढ़ बिताया है। अब वे इस साल राष्ट्रीय स्तर पर फेमिना मिस इंडिया 2024 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसकी आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त को की गई थी।

इस मौके पर उनके परिवार ने कहा कि वे विशाखा की इस सफलता से बहुत खुश और गर्वित हैं। विशाखा के परिवार में उनके माता-पिता और एक बड़ी बहन शामिल हैं। परिवार ने विशाखा के मॉडलिंग करियर में पूरा सहयोग दिया है। विशाखा के परिवार में सभी चाहते हैं कि विशाखा इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहें।

विशाखा के पिता, वी। के। राय ने बताया कि शुरुआत से ही विशाखा की रुचि मॉडलिंग, एक्टिंग और डांस में रही है। उन्होंने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र से की थी। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2024 का खिताब जीतने से पहले, विशाखा ने मॉडलिंग के लिए विशेष कोर्स किया और जॉय टाइम्स फ्रेश फेस की विनर भी रह चुकी हैं।

विशाखा ने अपने इंस्टाग्राम में अपनी मां के साथ एक स्टोरी लगाते हुए अपने फॉलोवर्स को बताया अपनी इस सफलता के पीछे की कहानी बताई है। उन्होंने लिखा- 18 साल की उम्र में ही शुरुआत कर दी थी, ठीक इसी समय, 3 साल पहले और अपने कथन का समर्थन करने के लिए मुझे यह प्यारा क्लिप मिला, जिसे हमने तब शूट किया था, जब मम्मी और मैं मेरा पहला वॉक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा विश्वास करें, यह बुरा था। लेकिन, यह एक शुरुआत थी।

बता दें विशाखा ने छत्तीसगढ़ के रिसाली (भिलाई) स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुणे का रुख किया और एससीएमसी से बीएजेएमसी (मास कम्यूनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की।

एकीकृत पेंशन योजना का राज्य में पेंशनरों ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ शासन से इसे तुरंत लागू करने की मांग

रायपुर। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली एकीकृत पेंशन योजना का पूर्व कर्मचारी नेता, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इसे कर्मचारियों की भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने वाला निरूपित कर स्वागत किया है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे तुरंत लागू करने हेतु मुख्यमंत्री से आग्रह किया है।

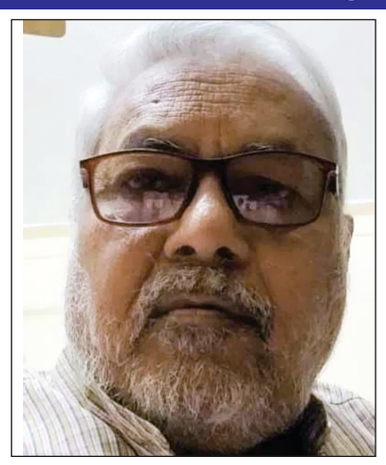

उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि इस योजना के तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी और 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी. वहीं अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय

मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा. सरकार इसके लिए एरियर का भी भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं.

पेंसनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश रायपुर के नेता क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, पुरानसिंह पटेल, सुरेश मिश्रा,द्रोपदी यादव, लोचन पाण्डे,अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, कुन्ती राणा,आर एन टाटी, ओ पी भट्ट,बी के वर्मा, दिनेश उपाध्याय,राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, प्रदीप सोनी, रमेश नंदे, रणविजय सोनी, आर जी बोहरे, एस के चिलमवार,बी एल यादव, सी एल चंद्रवंशी, हरेन्द्र चंद्राकर, नरसिंग राम, ओ डी शर्मा, मालिकराम वर्मा, अनिल तिवारी,के जी विसेंट, रामगोपाल श्रीवास्तव, व्ही टी सत्यम,नागेन्द्र सिंह, आर डी झाड़ी, एस एन देहारी, पी एन उड़कुड़े, जगदीश कनौजिया, एस के घाटोडे, मो कासिम, आर के नारद, आदि ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किए गए निर्णय को राज्य में तुरंत लागू करने की मांग की है।

ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने वाले दो नाबालिक सहित 5 गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। जिले के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माडेदा के ग्रामीण भीमा मंडावी पिता स्व दामा मंडावी उम्र 35 वर्ष पर 15 अगस्त 2024 के देर शाम जानलेवा हमला करने वाले ग्राम पोटाली के 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना करना स्वीकार करने से उक्त 4 आरोपियों को 16 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड लिया गया था। वहीं प्रकरण में विवेचना जारी रखते हुए शेष आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी अरनपुर के नेतृत्व में ग्राम पोटाली में आरोपियों की धर पकड़ हेतु दबिश दी गई और इस प्रकरण के दो विधि से संघर्षरत नाबालिक सहित कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिन्हें पूछताछ करने पर घटना में शामिल होना स्वीकार करने पर हीरेश मंडावी, जोगा मरकाम एवं हरीश मंडावी के विरूद्ध थाना अरनपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 12/2024 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2),191(2),141(1), 109 (1) के तहत सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं दो नाबालिगों को कायर्वाही उपरांत बाल सुधार गृह में भेजा गया।

कश्मीर का चुनाव क्यों है बेहद खास?

अनिल आनंद

जम्मू-कश्मीर के चुनावों को समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। और, इस बार तो वे दस साल के अंतराल के बाद और दूरगामी संवैधानिक बदलावों के बीच हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 से जुड़े इन बदलावों का असर न सिर्फ भौगोलिक रूप से, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी हुआ है। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के लोग अभी भी इस नए ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर संवेदनशील क्षेत्र तो रहा ही है, इसका चुनावी इतिहास भी बड़ा जटिल रहा है। इस बार खासकर कश्मीर घाटी पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो तीन दशकों के आतंकवाद के बाद अब कुछ हद तक सामान्य स्थिति में दिख रही है। हालांकि, जम्मू क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में आतंकवाद का नया दौर शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की राह में एक चुनौती साबित हो सकता है। कांग्रेस, नैशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। इसे इंडिया ब्लॉक गठबंधन कहा जा रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी गठबंधन भागीदार, महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बाहर रखा गया है। इसके पीछे स्थानीय रस्साकशी की भूमिका है और इस तथ्य की भी कि नैशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सबसे बड़ी ताकत है और जम्मू के कुछेक उन क्षेत्रों में भी प्रभाव रखती है, जहां पिछले एक दशक से भाजपा का दबदबा कायम है। इसमें दो राय नहीं कि एक मजबूत और एकजुट इंडिया., भाजपा को चुनौती देने की बेहतर स्थिति में होता। भाजपा न सिर्फ जम्मू में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही है, बल्कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नए रास्ते तलाश रही है। एकता के मोर्चे पर फारुख अब्दुल्ला और कांग्रेस नेतृत्व को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए था कि हालिया लोकसभा चुनावों में ही नैशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को जेल में बंद अलगाववादी इंजीनियर राशिद से मुंह की खानी पड़ी थी। यही नहीं, राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' और कुछ स्थानीय कारकों के कारण अनुकूल माहौल होने के बावजूद कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र में दोनों सीटें गंवा दी थी। यह सब 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में अधिक वोट हासिल करने के बावजूद हुआ। जम्मू और कश्मीर में लेकल फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं हैं। हालांकि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ये क्षेत्रीय रेखाएं कुछ हद तक धुंधली हो गई हैं। आज कुछ मुद्दों पर व्यापक सहमति है, जैसे राज्य का दर्जा वापस मिलना, भूमि और रोजगार अधिकारों का संरक्षण और रोज़ी-रोटी से जुड़े मुद्दे। जम्मू क्षेत्र हिंदू बहुल है, लेकिन जनसंख्या का मिश्रण अलग-अलग है। यहां भाजपा और इंडिया के बीच मुकाबला होना तय है। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमज़ोर है और पुराने नेताओं के दबदबे से मुक्त होकर नए और विश्वसनीय चेहरों को उतारने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन फिर भी वह गठबंधन में प्रमुख पार्टी है। इंजीनियर राशिद की घटना एक आश्चर्यजनक मोड़ है। तिहाड़ जेल के अंदर से बारामूला लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया जाना मतदाताओं में सहानुभूति पैदा कर गया। नतीजतन, उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यही स्थिति विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी? इस दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। इंजीनियर राशिद की नवगठित 'अवामी इत्तेहाद पार्टी' ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तरी कश्मीर के अलावा घाटी के अन्य हिस्सों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्पष्ट है कि लोकसभा में अप्रत्याशित जीत दर्ज करने के बाद इंजीनियर राशिद के समर्थक विधानसभा चुनाव में उस कामयाबी को दोहराना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कश्मीर घाटी में डॉ. अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है, वह है अलगाववादी और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी का चुनाव में शामिल होना। जमात के संगठनात्मक कार्य का संचालन करने वाली आठ सदस्यीय समिति के प्रमुख गुलाम कदीर लोन ने घोषणा की है कि जमात चुनाव में भाग लेने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे इंजीनियर राशिद गैरकानूनी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में है, वैसे ही जमात-ए-इस्लामी पर भी केंद्र सरकार 2019 में ही प्रतिबंध लगा चुकी है।

दलित वोटों की लड़ाई में सपा-बसपा आमने-सामने

अजय कुमार

मोदी सरकार ने उच्च पदों पर नौकरियों में सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) का अपना एक फैसला क्या वापस लिया, विपक्ष ने इसे मोदी को घेरने का हथियार बना लिया। पूरा विपक्ष अपनी पीठ ठोंक रहा है। पीठ ठोंकने वालों में यूपी के नेता मायावती और अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तो लगता है कि इससे यूपी की राजनीति की धुरी ही बदल जायेगी। बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई थी कि उनके तीव्र विरोध के बाद सरकार ने सीधी भर्ती वाला निर्णय वापस लिया है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। मतलब यह है कि फैसला केंद्र ने वापस लिया लेकिन अखिलेश और मायावती खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे सियासत इसी को कहा जाता है।

वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है कि परस्पर विरोधी बसपा और सपा नेताओं के सुर एक जैसे सुनाई पड़ रहे हों, इसी तरह के सुर आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर भी देखने को मिले थे, जब बसपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश ने भी तुरंत इसके समर्थन में पोस्ट लिख कर अपना पक्ष रख दियस। बात यहीं तक सीमित नहीं है, आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के सुर एक हैं?

या दोनों के बीच एक रेस लगी हुई है कि दलितों और पिछड़ों का ज्यादा हितैषी कौन है? आखिर इस मुद्दे के जरिए मायावती और अखिलेश कौन-सी राजनीति साध रहे हैं?

इस तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थितियों और नतीजों पर गौर करना जरूरी है। यूं तो संविधान और आरक्षण बसपा का कोर मुद्दा रहे हैं लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का जो नारा और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर संविधान की रक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया था,उसका फायदा जब इंडिया गठबंधन को मिला तो बसपा सुप्रीमों को अपना राजनैतिक भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। इससे पहले मायावती को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सपा का यह दांव इतना अधिक कारगर होगा। नतीजे आए तो सपा ने यूपी में अकेले 37 सीटें जीत लीं। साथ में कांग्रेस को भी छह सीटों पर जीत हासिल हुई और बसपा का सफाया हो गया। वोट प्रतिशत भी खिसक कर मात्र करीब साढ़े नौ प्रतिशत पर आ गया। इससे साफ हो गया कि सपा के द्वारा बसपा के दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर ली गई है। तब से मायावती की एक ही कोशिश है कि किसी तरह अपना दलित वोटबैंक वापस लाया जाए। इसके लिए मायावती लगातार दलित हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण पर अपना मत दिया, तो मायावती की उम्मीद को पंख लग गये। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिए। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आई। इसे पूरी तरह गलत ठहराते हुए उन्होंने भाजपा के साथ ही सपा-कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी घेरना शुरू कर दिया। वह संसद में संविधान संशोधन लाने की मांग पर अड़ गईं। इस मुद्दे पर उन्होंने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के जरिए कई बयान दिए।

शुरुआत में कांग्रेस ने इस पर सधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मायावती के आक्रामक रुख को देखते हुए सपा ने भी खुलकर मोर्चा खोल लिया। इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी उठा,जिस पर सपा और बसपा दोनों ही आक्रामक दिखे। अखिलेश यादव को लगा कि अब यदि चुप रहे तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो दलित वर्ग उनके साथ जुड़ा है, कहीं वापस बसपा में न चला जाए। उन्होंने सीधी भर्ती के मामले में 2 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। मायावती भी अपने बयानों के जरिए इस मुद्दे पर आक्रामक रूख बनाये हुए हैं।

लब्बोलुआब यह है कि सपा और बसपा नेता लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी वही हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव के बाद कमिटियों का नए सिरे से गठन किया है। उनमें भी साफ झलक देखने को मिली कि दलितों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं, अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ा रहे हैं। संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक वह अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं। संसद में भी अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनवाया गया। मायावती की तरह मंचों से आंबेडकर और कांशीराम का नाम अक्सर लेते हैं। दरअसल, अभी यूपी में विधान सभा उपचुनाव होने हैं।

एकात्मता के स्वर — रामायण

आदि काव्य के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि ने परम पुरुषोत्तम वशरचनंदन श्रीरा? के चरित्र का विशवरूप में चित्रण किया है। चतुर्विशत्सहस्वाणि स्लोकानामुक्तवानुषिः। तथा सर्गशतान् पंथ, षट्कांण्डानि तथोत्तरम् ।। बा. का. 4/2 इसमे महर्षि ने चौबीस हजार स्लोक पाँच सौ सर्ग तथा उत्तर काण्ड सहित सालों फाण्डों का प्रतिपादन किया है। %काव्यबीज सनातनम सम्पूर्ण काव्यों का सनातन बीज इस रामायण का एकमक्षरं पुंसां महातकाशनम। एक-एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। यह महाकाव्य सात काण्डों से मिलकर बेना है।येधी बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड अरण्यकाण्ड, किष्किंधाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, और उत्तरकाण्ड। इस महाकाव्य में ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, तन्त्रशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, दर्शन व राजनीति शास्त्र आदि का वर्णन मिलता है। श्रीराम जी का सम्पूर्ण जीवन मर्यादाओं से पूरी तरह आवृत है। चराचर सहित राष्ट्रधर्म की रक्षा उनके जीवन का हेतु है। तभी तो विश्वामित्र के कहने से दुष्ट ताड़का का संहार किया तो शूर्पणखा को लक्ष्मण ने नाक-कान विहीन कर दिया। अहल्या को पीड़ा से मुक्त किया। धनुषभंग कर राजाओं के गर्व को ही चूर नहीं किया बल्कि इक्कीस बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को करने वाले परशुराम की शक्ति को लौटते समय सीमित कर दिया। पिता के वचन पालन कर वन में जाकर %भुजाभ्यां साधुव्रताभ्यां वनवासी गुह निषाद को अपनी भुजाओं से आलिंगन किया, वहीं भीलनी शबरी के आश्रम पर जाकर उसके आतिथ्य को स्वीकार किया। देश और नारी के सम्मान की रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने वाले पक्षीराज जटायु का दयाह रामो धर्मात्मा दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। भरत को साग्रह राज्य करने अयोध्या लौटा दिया तो बाली के मरने के बाद विशाल राज्य का स्वामी सखा सुग्रीव को बना दिया। दुर्जयी रावण का अंत कर कहा भरणान्तानि वैराणि निव्रतं नः प्रयोजनम युद्ध का. 111/110 बैर मरने तक ही रहता है और प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है। सोचे की लंका के पद पर विभीषण का राज्याभिषेक कराते हैं। श्री राम का सखा भद्र जब यह कहता है कि नगर के लोग कहते हैं हत्या चं रावण संख्ये सीतामाहृत्य राघवः ।। 43/16 कि राम रावण को मारकर सीता को अपने घर ले आए। सीता के चरित्र को लेकर उनके मन में कोई रोष या अमर्ष नहीं है। लक्ष्मण से राम कहते हैं श्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे। क्ल सवेरे तुम गंगायास्तु परे पारे। सीता को गंगा के उस पार तमसा तट पर छोड़ आओ। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सत्य पवित्र सीता का भी निर्वासन।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-4)

गतांक से आगे...

आर्यसमाज की इस अनधिकार चेष्टा पर हम स्वयं कुछ न कह कर आर्यसमाज के एक कट्टर भक्त के शब्दों को उद्धृत करते हैं जो आपने इन मूसापन्थियों की कतर-ब्योंत से उब कर कहे हैं, पढ़िये - पं. नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ लिखते हैं- इस गीता को अपने मत में ढालने के लिए स्वामी जी ने तो कोई यत्न नहीं किया था परन्तु उसके पीछे कतिपय अनुयायियों ने विचित्र प्रयत्न किये।

सबसे प्रबल प्रयत्न भीमसेन शर्मा इटावा निवासी ने किया था। आपने जिस जिस श्लोक में भी अहं या मां पद देखा झट उस श्लोक को अर्धचन्द्र देकर बाहर निकाला और लगभग 238 श्लोकों को प्रक्षिप्त बतलाया। इसके पश्चात् दूसरा प्रबल प्रयत्न - हम प्रबल प्रयत्न इसलिये कहते हैं कि श्लोकों को प्रक्षिप्त बताकर अपने मतानुकूल संगति लगाना सहज कार्य था परन्तु श्लोकों को रखते हुए अपने मत में ढालना जरा कठिन बात थी। परन्तु ऐसा प्रबल प्रयत्न - कतिपय माननीय वृद्धों की ओर से हुआ (शायद यह इशारा पं. आर्यमुनि की ओर है) उन्होंने जहां जहां अहं पद देखा वहां ईश्वर अर्थ किया और माँ से वैदिक धर्म लिया। बस कुरुक्षेत्र की गीता एक दम अपना स्वरूप बदल कर गुफा में बैठकर ध्यानयोग सिखाने वाली पुस्तक बन गई और गीता का वह सुन्दर स्वरूप दूर जाता रहा औरं गणेशं कुर्वाणो वानरं चकार यह उक्ति सर्वथा चरितार्थ हो गई। श्री पं. भीमसेन जी की गीता में एक बात तो थी कि श्लोक के निकालने पर भी गीता का स्वरूप विकृत न हुवा था। पर हमारे वृद्ध महानुभावों की गीता कुछ की कुछ बन गई। हमारी समझ में यह दोनों प्रकार के प्रयत्न उचित नहीं थे। प्रक्षिप्त, अनुक्षिप्त और विक्षिप्त का प्रत्येक ग्रन्थ में अड़ंगा लगाने वाले हमारे आर्य भाई उत्साह की भी कोई अवधि है। वहु उत्साह ग्रन्थों की कतर ब्योंत में नहीं लगाना चाहिये। **क्रमशः ...**

श्री कृष्ण जन्माष्टमी

दिव्यांशी भदौरिया

जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का जश्न मनाने का पर्व है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, जो धर्म में गिरावट और अधर्म में वृद्धि होने पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार हिंदू धर्म के चार युगों में से तीसरे युग द्वापर युग के दौरान हुआ था। जन्माष्टमी का त्यौहार उपवास रखकर, भक्ति गीत गाकर, कृष्ण के जीवन के दृश्यों का अभिनय करके तथा मध्य रात्रि में प्रार्थना करके मनाया जाता है, जिसे उनके जन्म का समय माना जाता है।

ज्योतिष के मुताबिक, जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह

त्यौहार 26 अगस्त को है। इस बार उपाय करने का शुभ समय 25 अगस्त को रात्रि 9ः20 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त को रात्रि 10ः34 बजे तक रहेगा।

ऐसा माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दम्पतियों को इस दिन भगवान कृष्ण की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए, इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा भक्तगण उनके पसंदीदा व्यंजन का भोग लगाते हैं।

इस साल एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल के जन्म का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक रूप से खीरा काटा जाता है। इस साल इस समारोह में चांदी के सिक्के का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, लड्डू गोपाल के आगमन पर शंख बजाना चाहिए, जो भगवान विष्णु की पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

इन चीजों को भी फॉलों करें

-पूजा कक्ष को ताजे फूलों, दीयों और भगवान कृष्ण की पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों से सजाएं।

- लड्डू गोपाल को हाथ से बनी मालाओं से सजाएं।

- पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी जैसे पारंपरिक कपड़े पहनें।

-भगवान कृष्ण के लिए भोग और माखन तथा मिठाइयों सहित अन्य विशेष व्यंजन तैयार करें।

- भगवद गीता या कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित अन्य साहित्य के अंश पढ़ें।

- हरे कृष्ण मंत्र या भगवान कृष्ण को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप करें।

-भगवान कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि तक जागते रहें।

- जैसे-जैसे शुभ समय नजदीक आता है, प्रार्थना, ध्यान और भक्ति संगीत में शामिल हों।

भारत को लेकर क्यों नरम पड़े मुइज्जू

प्रणव ढल सामंता

अस्थिरता के भंवर में फंसे पड़ोसी मुल्कों की सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। पिछले साल मालदीव में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे, जब मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी भावनाओं के सहारे सत्ता में पहुंचे। 2022 में श्रीलंका में बांग्लादेश जैसा ही दृश्य नजर आ रहा था।

भारत ने श्रीलंका में शानदार वापसी की है। चीन के मुकाबले अब वहां भारत काफी मजबूत स्थिति में है। और अगर विदेशमंत्री एस जयशंकर के हालिया मालदीव दौरे की रोशनी में देखा जाए तो मुइज्जू भी अपनी गलती सुधारने की राह पर हैं। साफ है कि बदलती भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताएं भारत के बढ़ते प्रभाव की नई कहानी सुना रही हैं।

मिसाल के तौर पर मालदीव को लिया जाए। मई महीने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे चीन के बढ़ते कर्ज को लेकर चेतावनी दी। एक महीने बाद रेटिंग एजेंसी फिच ने उसकी रेटिंग कम कर दी। एजेंसी का आकलन था कि कम होता विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ता विदेशी कर्ज नई सरकार के लिए कठिन चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मालदीव के कुल विदेशी कर्ज का 30 फीसदी चीन से लिया गया है जो 4 बिलियन डॉलर से ऊपर बैठता है। जिस चीनी कर्ज के जाल में श्रीलंका फंसा, उसमें कई और छोटी अर्थव्यवस्थाएं फंसीं। मुइज्जू को यह समझते देर नहीं लगी कि उन्हें भारत की मदद की जरूरत है।

इस बीच भारत पर निर्भरता कम करने के लिए पश्चिम एशिया से खाद्य आपूर्ति शुरू कराने जैसे मुइज्जू के प्रयासों के परिणाम यह हुआ कि मालदीव में इन सामानों के दाम बढ़ गए। जल्दी ही साफ हो गया कि खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

के लिहाज से मालदीव के लिए भारत ही सबसे अच्छा विकल्प है।

श्रीलंका में भी 2022 का संकट अभी तक भारत के लिहाज से फायदेमंद ही साबित हुआ है। कोलंबो में वित्तीय संकट आने पर भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। अहम मौकों पर लिक्विडिटी उपलब्ध कराई और फिर द्रुस्त्र पैकेज सुनिश्चित करने में भी सहायता की। आज श्रीलंका में महंगाई दर 3 फीसदी से नीचे है जबकि सितंबर 2022 में यह 67.4 फीसदी थी।

जहां तक चीन से जुड़ी चिंताओं का सवाल है तो कोलंबो ने श्रीलंकाई समुद्री सीमा में विदेशी रिसर्च जहाजों को पहले ही बैन कर दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अगले साल समाप्त होने वाला है लेकिन चीन की ओर श्रीलंका के बढ़ते रुझान की समस्या अब समाप्त हो चुकी है। इसी साल श्रीलंका में होने वाले चुनावों के मद्देनजर भारत भी खासा सतर्क है और सत्ता के सभी दावेदारों से बातचीत कर रहा है।

ऐसे में दो बातें गौर करने लायक हैं। एक, किसी पड़ोसी देश में पैदा हुए किसी संकट पर भारत हमेशा काबू पा ले या उसे हल कर दे यह जरूरी नहीं है। दो, भारत ऐसे संकट को अवसर में जरूर तब्दील कर सकता है, खासकर मौजूदा भू राजनीतिक संदर्भों में। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि भारत के अपने मजबूत इकॉनमिक प्रोफाइल की बदौलत इस क्षेत्र में उसका आर्थिक प्रभाव भी बढ़ा है।

पिछले एक दशक में भारत ने खास तौर पर चार प्रमुख क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत की हैं- फाइनैंस, सप्लाई चेन, पेट्रोलियम और इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन क्षेत्रों में किया गया निवेश अब राजनीतिक संकटों के दौरान स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाता है। आपसी रिश्तों के समीकरणों की बदौलत निर्भरता के धागों में उलझे इन देशों की हर सरकार संकट की स्थिति में भारत का समर्थन सुनिश्चित करना चाहती है।

नेपाल में भारत ने तीन और ट्रांसमिशन लाइन स्थापित कर दी है। इससे अब काठमांडू अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हाल ही में बिजली खरीद का एक समझौता हुआ है। त्रिपुरा के एनटीपीसी प्लांट और झारखंड (गोड्डा) के अडाणी पावर प्लाटं से बांग्लादेश को सप्लाई शुरू हो चुकी है।

बांग्लादेश की कोई भी नई सरकार थोड़ी सी स्थिरता पाते ही भारत के साथ आर्थिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया दुरुस्त करना चाहेगी। भारत के जितने भी संभावित विकल्प हैं, आगे चलकर ज्यादा जोखिमभरे और महंगे साबित होते हैं। चीन के विपरीत भारत न तो अपनी मदद को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और न ही इन देशों की संप्रभुता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करता है। इसके अलावा यह बात भी है कि भारत का हित आर्थिक तौर पर समृद्ध पड़ोस सुनिश्चित करने में है क्योंकि इनमें से किसी भी देश में आया संकट आसानी से भारतीय भूक्षेत्र में प्रवेश कर सकता है।

इस तरह व्यापक भू राजनीतिक समीकरण भारत के पक्ष में नजर आते हैं, आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है। शेख हसीना सरकार को लेकर भारत और अमेरिका की राय अलग-अलग है। लेकिन क्या वे इस असहमति का फायदा चीन को उठाने देंगे? भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी की अहमियत को देखते हुए दोनों देशों का हित इसी में है कि वे इन असहमतियों को आपस में ही हल करने की कोई राह निकाल लें।

आज का इतिहास

1894 नीदरलैंड सामाजिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी स्थापना की गयी।

1910 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का युगोस्लाविया के स्कोपजी में जन्म हुआ।

1920 अमेरिका 19वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को मताधिकार मिला।

1920 संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के उन्नीसवीं संसद में महिलाओं के मताधिकार की गारंटी को पारित किया गया।

1928 स्कॉटलैंड के पैस्ले के एक कैफे में, मई डोनॉग्यू ने अदरक बीयर की बोतल में एक घोंघे को पाया, जिससे वह ब्रिटिश आम कानून, डोनोगह्यू वीटेवेंसन में से एक लैंडमार्क सिविल एक्शन मामलों को लॉन्च करने लगा।

1929 अमेरिका ने पहले रोलर कॉस्टर का निर्माण किया।

1945 यह खुलासा किया गया है कि मैनहट्टन परियोजना में 25,000 से अधिक चूहों का उपयोग किया गया था, यह देखने के लिए कि क्या परमाणु बम संयंत्रों में श्रमिकों पर विकिरण का कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा।

1968 अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शिकागो के इन-स्टैटिस्टिकल एम्फीथिएटर में शुरू हुआ, जो चार दिनों के संघर्ष के दौरान वियतनाम विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस को पटखनी देता है।

1968 यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शिकागो के इंटरनेशनल एम्फीथिएटर में शुरू हुआ, जिसमें वियतनाम विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच चार दिनों की झड़पें हुईं।

1970 बेटी फ्रीडान और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन ने न्यूयॉर्क शहर में समानता के लिए महिलाओं की हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें 20,000 महिलाओं ने लैंगिक समानता की निरंतर कमी का विरोध किया।

1977 क्यूबेक की नेशनल असेंबली ने फ्रेंच को क्यूबेक की एकमात्र भाषा घोषित किया।

1982 नासा ने टेलीसेट-एफ का प्रक्षेपण किया।

1994 इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का प्रयोग किया गया।

2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवीनतम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के 174 देशों के 60,000 प्रतिनिधि और राजनेता एक साथ आए हैं।

अगर हमें 'विश्व मित्र' बनना है तो...बदलना होगा पड़ोसियों से अपना व्यवहार

रामचंद्र गुहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में सरकार के समर्थकों ने यह दावा किया कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। बार-बार कहा गया कि हमारी सभ्यतागत गहराई, समृद्ध दार्शनिक परंपराएं और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रथाओं ने हमें संस्कृति के मामले में हमेशा अग्रणी रखा है। अब भारत आर्थिक और तकनीकी तौर पर सफल है। वैश्विक नेतृत्व भी इससे पूरी तरह आश्वस्त है। इस दावे को व्यक्ति केंद्रित रखा गया और कहा गया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए विदेश में जी-20 बैठकों की मॉर्फ्ड तस्वीरें सामने आईं, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री को एक भव्य इमारत की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आदि चुपचाप उनके पीछे चल रहे थे। इस तरह के प्रचार का कुछ हद तक असर भी हुआ। वर्ष 2023 में भारत द्वारा जी-20 की बारी-बारी से अध्यक्षता संभालने के बाद मेरे एक मित्र ने दिल्ली मेट्रो में किसी को यह कहते हुए सुना, आपको पता है कि मोदी जी केवल हमारे देश के नहीं, बीस देशों के प्रधानमंत्री हैं!

उसी समय एक बदलाव पार्टी के प्रचार की दुनिया में उभरकर सामने आया। कहा जाने लगा कि भारत विश्व मित्र है। यह मोदी शासन की महत्वाकांक्षाओं का स्पष्ट रूप से अवमूल्यन था। भारत अभी दुनिया को सिखाने की स्थिति में नहीं था, फिर भी वह दुनिया के हर देश से दोस्ती करने की अनोखी स्थिति में था। अपनी बड़ाई खुद करने की यह स्थिति भारतीय राजनीति में क्यों आई, इसके बारे में अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि दिल्ली मेट्रो में बैठे भक्तों के विपरीत शासन के प्रचारकों को पता था कि भारत की जी-20 अध्यक्षता बहुत अस्थायी है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी? या हमारी अर्थव्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी? या फिर हमारी सीमा पर चीनी घुसपैठ और प्रधानमंत्री की उसके बारे में बोलने की अनिच्छा ने वैश्विक नेतृत्व के हमारे दावों को खोखला बना दिया? तथ्य यह है कि विमर्श में एक स्पष्ट बदलाव आया था। सत्ता पक्ष के शांत और यथार्थवादी समूहों में 'विश्व मित्र' शब्द का उपयोग पहले से कहीं अधिक बार किया जा रहा था।

हालांकि बांग्लादेश संकट के मद्देनजर इस हल्के, कम गंभीर अहंकार को भी त्यागने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि हमारे निकटतम पड़ोसी देशों के नागरिक भारत को एक विश्वसनीय या भरोसेमंद मित्र नहीं मानते हैं। कई बांग्लादेशी भारतीय इरादों को लेकर आशंकित हैं, जिसका मुख्य कारण मोदी शासन द्वारा शेख हसीना के निरंकुश तरीकों का उत्साहपूर्ण समर्थन है। पिछली जनवरी में जब शेख हसीना ने दोबारा हुए चुनाव में धांधली से जीत हासिल की थी, तब भी भारतीय चुनाव आयोग ने बांग्लादेशी चुनाव आयोग की तारीफ की थी। श्रीलंका और नेपाल में भी यह भावना साफ तौर पर मौजूद है कि भारत का व्यवहार पड़ोसी देशों के प्रति अहंकारपूर्ण है। इन तीनों देशों के नागरिकों द्वारा दिए गए एक संयुक्त बयान में यह कहा गया कि भारत सरकार को हमारी राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। कई सालों से कोलंबो, ढाका और काठमांडू में

नई दिल्ली के राजनीतिक, नौकरशाही और खुफिया तंत्र के दखल ने एक अंतहीन राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया है और निरंकुश शासन को बढ़ावा दिया है। इन आरोपों को एक खास अहमियत दी जाती है। इसलिए बांग्लादेश के इन लेखकों के बयान कि पिछले दशक में शेख हसीना के निरंकुश शासन को बढ़ावा देने में नई दिल्ली ने सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बदले में कई तरह की राजनीतिक और आर्थिक रियायत प्राप्त कीं। श्रीलंका के बारे में वे कहते हैं, आईपीकेएफ के समय से पहले और उसके बाद से श्रीलंका को अपनी राजनीति में नई दिल्ली के अतिक्रमण से बार-बार जूझना पड़ा है। इसके अलावा नई दिल्ली के अधिकारी सक्रिय रूप से भारतीय व्यापार समूहों को द्वीप पर व्यापार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बुद्धिजीवियों का ऐसा विचार है कि भारत ने हमेशा से एक दबंग बड़े भाई का किरदार निभाया है। 19वीं सदी में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा था, मेक्सिको ईश्वर से जितना दूर है, अमेरिका के उतना ही करीब है।

ऐसा नहीं है कि भारत के इरादे अभी ऐसे हो गए हैं। यह पहले से ही रहे हैं, जब राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहले नेपाल पर नाकाबंदी लगा दी थी। सही मायनों में वह हमारे पहले प्रधानमंत्री ही रहे होंगे, जो विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने ही इस संबंध में दिशा तय की होगी। जवाहरलाल नेहरू के साथ काम कर चुके राजनयिक जगत मेहता ने एक बार कहा था, नेहरू इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए या विदेश मंत्रालय ने उन्हें सही सलाह नहीं दी कि 20वीं सदी में अपने असमान पड़ोसियों के साथ कूटनीति स्थापित करना कितना मुश्किल हो सकता है? कम्युनिस्ट चीन ने मैकमोहन रेखा को कभी नहीं माना। उसका कहना है कि उससे हस्ताक्षर दबाव में कराए गए थे। उस समय वह पश्चिमी साम्राज्य के अधीन था। 1962 में चीन के आक्रमण ने भारतीयों के मन पर एक गहरा घाव दिया है। उसी तरह पाकिस्तान ने न सिर्फ जम्मू-कश्मीर, बल्कि देश के कई हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसे में उसके साथ मेल-मिलाप से मुश्किलें बढ़ती हैं। हालांकि छोटे पड़ोसी देशों के साथ इस तरह की समस्या नहीं है। इसके विपरीत कई ऐसे कारक हैं, जो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मसलन, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है और कई सांस्कृतिक समानताएं हैं। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद होने में मदद की। भारत और श्रीलंका का औपनिवेशिक इतिहास एक ही रहा है। ऐसे में अगर भारत और इन तीनों देशों के बीच संबंध कभी भी सहज नहीं रहे हैं तो यह बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र की ओर से आत्मनिरीक्षण की मांग करता है।

साल 2007-08 में जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तब भारत के 'सुपर पावर' बनने की बातें बहुत की जाती थीं। इस तरह के दावे समय से पहले थे। दुनिया पर वर्चस्व बनाने वाली सोच की जगह अपनी सामाजिक और राजनीतिक गलतियों में सुधार करना अधिक बुद्धिमानी थी। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में भारत को वैश्विक स्तर पर महान बनाने की बात कम हो गई। हालांकि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में यह बात फिर से उभरी और स्वदेशी के लेबल के तहत उसकी ब्रांडिंग की गई।

हमारा देश जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें संस्थाओं का नष्ट होना, बढ़ती असमानता, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद के अलावा पर्यावरणीय गिरावट शामिल हैं। ऐसे में भारत के विश्व गुरु बनने की बात का कोई मतलब नहीं है। हां, विश्व मित्र बनने वाली बात में दम लगता है। अगर भारत दुनिया के सभी देशों का दोस्त बनकर रहना चाहता है तो उसे अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार में बदलाव लाना होगा, खासतौर पर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ। इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें न सिर्फ उनके नेताओं, बल्कि नागरिकों के प्रति भी आदर और विश्वास का भाव दिखाना होगा।

विकसित भारत के संकल्प को रोकने रची गयी बड़ी साजिश

नीरज कुमार दुबे

भारत जब विकसित देश बनने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसकी राह में बाधाएं पैदा करने के लिए तमाम तरह की साजिशें की जा रही हैं। इनमें से एक साजिश है देश के युवाओं को नशे और अश्लीलता के दुष्चक्र में फंसाने की और यह साजिश काफी हद तक सफल होती भी दिख रही है। कॉलेजों के आसपास आसानी से मादक पदार्थ मिल जाते हैं, रेव पार्टियों का चलन देश में बढ़ चुका है, मोबाइल पर अश्लील कंटेंट आसानी से उपलब्ध है। इस सबसे युवाओं के दिलो-दिमाग पर बड़ा असर पड़ रहा है और वह अपनी असल जिम्मेदारियों से विमुख होकर भ्रमित हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए आज जो आधार तैयार किया जा रहा है उस पर इमारत युवाओं को ही आगे चलकर खड़ी करनी है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह युवाओं के जीवन और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

वैसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल पर ही अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, आप तमाम प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध वेब सीरीजों को देख लीजिये। अधिकतर में द्विअर्थी संवाद और अश्लील दृश्य भरे पड़े हैं। यही नहीं, हिंदी सिनेमा की भी कुछेक ही फिल्में ऐसी आती हैं जिन्हें परिवार के साथ देखा जा सकता है। हर जगह पसरी इस अश्लीलता का बाल मन पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसके चलते बाल्यकाल में ही छात्र गालियां सीख जा रहे हैं साथ ही अश्लील कंटेंट उन्हें गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जिसके चलते किशोरवय उम्र में ही शारीरिक संबंध बनाने या दुष्कर्म करने की खबरें आम हो रही हैं। खास बात यह है कि इस सब पर माता-पिता भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह खुद मोबाइल में व्यस्त हैं।

बहरहाल, इन सब स्थितियों से निकलने के लिए किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है जब हम आत्मचिंतन करें और देखें कि हमारा परिवार, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? समय आ गया है कि हम चिंतन करें कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का जो लक्ष्य रखा है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है? निश्चित ही आत्ममंथन से निकलने वाला अमृत देश के लिए और हमारे अपने लिये भी हितकारी होगा।

लेटरल एंट्री पर क्या विपक्ष के हाथ लग गई मास्टर की ?

अजय बोकिल

सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर मचे बवाल के तीन दिन बाद ही इस मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा यू-टर्न लेने का मतलब साफ है कि हाल के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस के हाथ संविधान और आरक्षण की वो मास्टर की लग गई है, जो मोदी सरकार की किसी भी पहल की भ्रूण हत्या कर सकती है। लेटरल एंट्री मामले में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर यह कहकर सवाल उठाए थे कि बिना आरक्षण प्रावधान से पिछले दरवाजे से यह सीधी भर्ती इस का सूचक है कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और आरक्षण को न मानना संविधान खत्म करने जैसा है। गौरतलब बात यह है कि मोदी सरकार ने लेटरल भर्तियां 2018 में ही शुरू कर दी थीं। लेकिन तब विपक्ष की ओर से भी इसका खास विरोध नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है।

सरकार इसका न तो कोई ठोस तोड़ खोज पा रही है और न ही विपक्ष के हमलों का पुरजोर राजनीतिक जवाब दे पा रही है। राहुल गांधी के अलावा खुद एनडीए के दो घटकों 'जद यू' और 'लोक जन शक्ति पार्टी' ने भी इन नियुक्तियों का सार्वजनिक रूप से विरोध कर दिया। हालांकि, सरकार में शामिल एक और घटक टीडीपी ने इसका समर्थन किया। बावजूद इसके सरकार ने संविधान और आरक्षण के मुद्दों को लेकर आसन्न राजनीतिक खतरों को भांपा और अपनी बात पर अड़े रहने की जगह बैक फुट पर जाना ही बेहतर समझा।

यह भी साफ हुआ कि एनडीए में लेटरल एंट्री पर एकमत नहीं है। कहने को मोदी कैबिनेट के प्रवक्ता और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कमजोर पलटवार जरूर किया कि लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले कांग्रेसनीत यूपीए सरकार में ही आया था। लेकिन अब कांग्रेस ही इसका विरोध रही है।

दरसअल, मोदी 1.0 व 2.0 के ठीक उलट मोदी 3.0 में सरकार को कोर मुद्दों पर बार- बार बैक फुट पर जाना रहा है। मसलन वक्फ बिल सरकार ने संसद में पेश तो किया लेकिन व्यापक विरोध के चलते उसे जेपीसी के पास भेजना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे भी भाजपा की रणनीति देख रहे हैं। इसी तरह समान नागरिक संहिता (जिसे अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं), के मानसून सत्र

में संसद में पेश किए जाने की चर्चा थी। लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

अब लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार ने यू टर्न लेकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे यह आशंका सही साबित हो रही है कि एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता संचालन के पिच पर उस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी नहीं कर पाएगी, जैसी कि वो पूर्व के दो कार्यकालों में कर सकी थी। दूसरे कार्यकाल में केवल तीन विवादित कृषि कानूनों का मुद्दा ही ऐसा था, जब मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन अब यह बार बार होता दिख रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री की विधिवत शुरुआत मोदी 1.0 में 2018 में हुई। तब पहली बार 9 विशेषज्ञों को केन्द्र सरकार के अलग-अलग विभागों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों पर सवाल तो तब भी उठे थे, लेकिन कोई राजनीतिक बवाल नहीं मचा। इन 9 विशेषज्ञों का चयन भी यूपीएससी ने 6077 आवेदनों में से किया था। इसमें किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां 3 से 5 साल तक के लिए की गई थीं। इनका कोई अलग से कैडर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से हटना था।

बीते 6 सालो में हुई लेटरल एंट्रियों के जरिए भर्ती हुए विषय विशेषज्ञो का क्या परफार्मेंस रहा, प्रशासन को और कार्यक्षम बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, यह प्रयोग कितना सफल और कितना जरूरी समझा गया, आईएएस के एक सुगठित और जटिल जाल में लेटरल एंट्री छाप अधिकारी कितनी आजादी से काम कर पाए, उनकी काबिलियत का सरकारी तंत्र में कितना सदुपयोग हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

फिर भी सरकार ने ये भर्तियां जारी रखी हैं, इसका अर्थ यही मानें कि वह इन लेटरल एंट्री नौकरशाहों के काम से संतुष्ट रही होगी। लेकिन तब और अब में राजनीतिक फर्क यह है कि जब लेटरल एंट्री सूत्र पर अमल शुरू हुआ तब इसे सरकार में कारपोरेट मानसिकता की सीधी एंट्री और पूंजीवाद के फैलते जाल के रूप में देखा गया था, जिसकी प्राथमिकताएं लोकसेवक से अलग और एक संस्थान को हर हाल में मुनाफे में चलाने के आग्रह से निर्देशित होती हैं।

'जनसेवा' वहां केवल पैसे के बदले दी जाने वाली 'सर्विस' और तकनीकी गुणवत्ता ग्राहक को संतुष्ट के करने के भाव से तय होती है ताकि उपभोक्ता कंपनी से न सिर्फ जुड़ा रहे बल्कि बार उसकी सेवाएं लेता रहे। जबकि एक लोकसेवक संविधान और चुनी हुई सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोक प्रशासन का अपना एक विशाल और बेहद जटिल तंत्र है, जो कई गुणों और दोषों से भरा हुआ है। इसमें भी चंद लोग नवाचारी निकल आते हैं। कई भ्रष्टाचार को ही 'लोकसेवा' मान लेते हैं तो ज्यादातर अपनी गर्दन बचाकर नौकरी करते जाने को ही लोकसेवा मानते हैं।

इस तंत्र में प्रतिस्पर्द्धा पेशेवर अथवा गुणवत्ता के बजाए मलाईदार पोस्ट हथियाने और राजनीतिक आकाओ को खुश रखने की ज्यादा होती है। दूसरी तरफ कारपोरेट क्षेत्र से आने वाले विशेषज्ञ तुलनात्मक रूप से ज्यादा आजादी ,कड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा और न्यूनतम जवाबदेही के माहौल के काम करने आदी होते हैं। वहां प्रतिस्पर्द्धा अपना 'बेस्ट' देने के आग्रह से ज्यादा संचालित होती हैं। हालांकि, व्यवसायगत चालाकियां और दुरभिसंधियों का बोलबाला वहां भी है, लेकिन मालिक को साधकर काफी कुछ साधा जा सकता है।

ऐसे में लेटरल एंट्री भारत के जटिल प्रशासनिक तंत्र में कितनी कारगर है, यह अध्ययन का विषय है। ऐसे लोग एक रूढ़िवादी और जड़ मानसिकता भरे तंत्र में कुछ नया करना चाहें भी तो उनके पास समय बहुत कम होता है। महज 3 या 5 साल की नौकरी में कोई बड़ा नवाचार वो कर पाते होंगें, कहना मुश्किल है। शीर्ष पदों पर तो यह फिर भी संभव है, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी और निदेशक पदों पर यह ज्यादा मुश्किल है, जहां आदेश का ठीक से पालन कराना ही पहला काम है।

अब आंदोलनों से जागतीं राजनीतिक उम्मीदें

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र सरकार की 'लाड़ली बहन योजना' आरंभ होने के बाद विपक्ष में बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक था, लेकिन हर घटना में राजनीति ढूंढ़ने में माहिर होते राजनीतिक दल चुनौतियों के आगे रास्ता खोज ले रहे हैं। पहले सवाल का जवाब दिया जाता था, अब आंदोलन का उत्तर दूसरे आंदोलन से दिया जा रहा है। उसमें थोड़ा आगे बढ़ें तो अनुमान धरना-प्रदर्शन की तीव्रता से उत्पन्न ताकत से लगाया जा रहा है।

बंद हो या प्रदर्शन या फिर तोड़-फोड़ की घटनाएं, यदि उनमें राजनीति का जोड़ लगता है तो समस्याएं अपनी जगह रह जाती हैं और उनकी संवेदनशीलता को एक नया मोड़ मिल जाता है। रही न्याय की बात तो वह जहां की तहां बनी रह जाती है, जिससे आम आदमी का प्रत्यक्ष संबंध है।

राज्य में जब से लाड़ली बहन योजना आरंभ हुई, तब से उसे महिलाओं की हितैषी कम, चुनावी स्वार्थ से जुड़ी योजना बताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। यहां तक कि अनेक सत्तारुढ़ दल के नेताओं ने भी हल्के अंदाज में उसे चुनाव से जुड़ा बताया है। हालांकि राज्य का नेतृत्व योजना की गंभीरता कम करता नहीं दिखा। यहां तक कि अनेक संशोधन कर महिलाओं की शिकायतों और परेशानियों को दूर किया गया।

वैसे राज्य विधानसभा के चुनाव समीप आते देख योजना के लाभ-हानि पर विचार किया जाना स्वाभाविक स्थिति थी। इसी बीच, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के बाद बदलापुर के स्कूल में हुई घटना ने विपक्ष को नया हथियार हाथ में दे दिया, जिससे सरकार पर ही केवल प्रहार नहीं हुआ, बल्कि सरकारी योजना पर भी सीधा निशाना लगा। एक बड़ी घटना से राज्य की अनेक दब जाने वाली घटनाएं सामने आ गईं। जिन पर न चाहते हुए भी राज्य सरकार को संयम दिखाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आम तौर पर किसी घटना पर जनआक्रोश गलत नहीं माना जा सकता है, किंतु उसमें राजनीतिक दलों का आग में घी डालना और अपने भविष्य की चिंता को आम आदमी की परेशानियों से हल्का करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बावजूद इसके चुनावी मौसम में हर दल अपने विरोधी की गलतियों को ढूंढ़ कर आंदोलन करने में

जुटे हैं। कभी किसी नेता का बयान तो कभी सरकार या प्रशासन की गलती आंदोलन का बहाना बन जाती है।

आम तौर पर आंदोलनों को विपक्ष की भूमिका का भाग माना जाता है। लेकिन राज्य में सत्ता पक्ष भी विपक्ष की कमजोरियों को ढूंढ़ आंदोलन करने में नहीं हिचकिचा रहा है। बांग्लादेश की घटनाओं के बहाने भगवा दल हिंदू संगठनों को सक्रिय कर रहे हैं, तो विपक्ष हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पर सरकार को घेर रहा है। उसके पास वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार के विधेयक से लेकर मुंबई की धारावी बस्ती तक के आक्रामक हथियार हैं। सत्ता पक्ष के पास आंदोलनों के खिलाफ आंदोलन की राह है, जो उसने पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) और धनगर समाज के आंदोलन के बहाने दिखाई। इनसे उसे राजनीतिक लाभ तो सीधे तौर पर नहीं मिला, लेकिन समाज के ध्रुवीकरण में आसानी हुई।

सत्ता पक्ष और विपक्ष से परे राज्य में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, किसान आंदोलन अपनी जगह अपनी मांगों को रख रहे हैं। परंतु परोक्ष रूप से सभी आंदोलनों के पीछे राजनीतिक दलों की भूमिका की ओर इशारा किया जा रहा है। हालांकि आंदोलनकारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सहयोग से इंकार ही नहीं करते, बल्कि उनकी आलोचना भी करते हैं। किंतु चुनावों को देख चर्चाओं को हवा मिलती रहती है। हर विपक्षी दल मन ही मन सरकार के खिलाफ आंदोलन को अपने पक्ष में मान कर खुश होता रहता है। यूं देखा जाए तो चुनाव को लेकर बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जिन पर उसे राहत की अपेक्षा है। मगर सरकार जन समस्याओं को अपने ढंग से निपटाने का दावा करती है और उसे विपक्ष बार-बार खोखला साबित करता है।

'लाड़ली बहन', 'लाड़ला भाई' और इसी तरह की किसानों के लिए योजना की राज्य सरकार ने बात की है। जो कुछ हद तक ये बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दिक्कतों को दूर करने में सहायक हो सकती है। मगर इनका प्रभाव कितने दिन रहेगा और इनके क्रियान्वयन के बीच होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं सकारात्मक माहौल को कैसे बनाए रख पाएंगी, यह ध्यान देने योग्य होगा। बदलापुर की घटना के बाद लाड़ली बहन की आर्थिक सहायता से सुरक्षा पर अधिक माहौल तैयार हुआ है, जिसको लेकर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है।

फिलहाल लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का सभी को अधिकार प्राप्त है और वह उस स्थिति में अधिक जायज हो जाता है जब कहीं अन्याय, अत्याचार और असंतोष की स्थिति हो। मगर राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले आंदोलनों की ध्वनि और विचार भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाते हैं। कुछ माह में राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दलों की सक्रियता स्वाभाविक है। किंतु उसमें यदि आम जनता की परेशानियों और जरूरतों के प्रति ईमानदारी बनी रहे तो अधिक बेहतर है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के गठबंधन दलों ने विधानसभा के कार्यकाल में आधा-आधा समय सत्ता भोगी है। इसलिए दोनों के कार्यकाल के अच्छे-बुरे प्रसंग सामने हैं। केवल मत मांगने के लिए एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना और खुद को बेहतर बताना जन समस्याओं का हल नहीं है। वास्तविकता की जमीन पर समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं। सत्ता पाकर उनसे मुंह चुराना कुर्सी बचाने का खेल हो सकता है और सत्ता से दूर जाते ही आंदोलनों से वापसी की कोशिश में जुटना नैतिक नहीं माना जा सकता है। जिम्मेदारियों के निर्वहन में चूक स्वीकार कर ईमानदारी से सत्ता में वापसी के प्रयास करना जन अपेक्षा पर खरा उतरना माना जा सकता है। शोर-शराबे, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी के आंदोलनों से अधिक समय तक राजनीतिक उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। परदे के आगे और परदे के पीछे 'पब्लिक' सब जानती है।

बांग्लादेश में पहले सुधार, फिर चुनाव, लेकिन अनिर्णय की स्थिति से कुछ दल असहज

सुबीर भौमिक

अशांत बांग्लादेश में तुरंत संसदीय चुनाव कराने की संभावनाएं इस हफ्ते तभी धूमिल हो गईं, जब मुल्क की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनाव की कोई निश्चित समय-सीमा बताने से इन्कार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें पहले देश में महत्वपूर्ण सुधार करने का जनादेश मिला है। जाहिर है, यह बात बांग्लादेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, अपदस्थ अवामी लीग और प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसकी सहयोगी जमात-ए-इस्लामी को अच्छी नहीं लगेगी। बीएनपी मुल्क के मौजूदा मिजाज का लाभ उठाना चाहती है, जो अवामी लीग के खिलाफ है और सत्ता में लौटना चाहती है। यह तभी संभव होगा, जब चुनाव जल्द कराए जाएं।

बीएनपी नौकरशाही, पुलिस और सुरक्षा सेवाओं तथा सरकार के अन्य विभागों में चल रहे बदलाव का स्वागत कर सकती है, जहां अवामी लीग के करीबी लोगों को कार्यकारी आदेशों या छात्र आंदोलनकारियों द्वारा ?हटाया जा रहा है। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दो घंटे की अंतिम चेतावनी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, वह एक तरह का जबरन बदलाव है। वहीं, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने %तीन महीने के भीतर नए चुनाव% कराने के लिए भारत से हस्तक्षेप करने की मांग की है। शायद चुनावों की घोषणा से सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चल रही साजिशें कम हो जाएं और अवामी लीग को स्वच्छ छवि वाले नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का मौका मिल जाए, ताकि हसीना के अपदस्थ होने के बाद अनियंत्रित अराजकता और लूट से नाराज जनभावनाओं का फायदा उठाया जा सके। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके चुनावों में देरी कर सकते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने प्रेस सचिव शफीकुल आलम के माध्यम से यूनुस को उद्धृत करते हुए लिखा, %सत्ता में बने रहने के प्रयास में?हसीना की तानाशाही ने देश की हर संस्था को नष्ट कर दिया।

यूनुस नेअंतरराष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में शरण लिए हुए दस लाख से अधिक रोहिंग्याओं को सहायता देना जारी रखेगी। लेकिन उनकी असली परीक्षा आर्थिक विकास को पटरी पर लाना है, जो कोविड के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुई है और भ्रष्टाचार के कारण बैंक डिफॉल्ट और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के कारण और बदतर हो गया है। यूनुस को सख्ती से वित्तीय अपराधियों से निपटना होगा।?सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान यूनुस ने अपनी राजनीति पार्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पीछे हट गए। अटकलें हैं कि वह बीएनपी-जमात गठबंधन एवं अवामी लीग के बीच लंबे समय से चल रही मुल्क की द्विदलीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए इस बार नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। चुनाव में देरी से वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। अमेरिका और यूरोपीय संघ इसका स्वागत कर सकते हैं। भारत तब तक बीएनपी-जमात सरकार के बजाय अंतरिम प्रशासन को प्राथमिकता दे सकता है, जब तक कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर लेता। चीन, जिसने भारत की तरह हसीना का समर्थन किया है, सत्ता में आने वाले किसी से भी निपट सकता है।

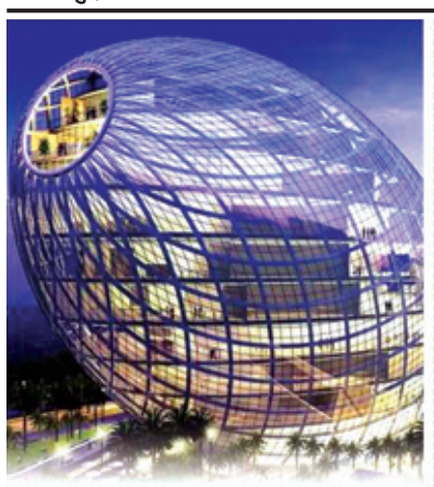

अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है मुंबई की यह बिल्डिंग

दुनियाभर में अपने आर्किटेक्चर को लेकर कई इमारतें प्रसिद्ध हैं, लेकिन भारत की बात करें तो मुंबई की एक इमारत अपने अनोखी बनावट के लिए बेहद लोकप्रिय है। मुंबई में जेम्स लॉ साइबरटेक्चर बिल्डिंग का डिज़ाइन देखने में बहुत अलग है। यह इमारत आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। 13 मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग अंडे के आकार की है। यह इमारत बनाने में कंक्रीट, स्टील और ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस इमारत को हांगकांग की एक फर्म ने डिजाइन किया है। यह इमारत एन्वायरनमेंटल डिजाइन, शानदार कंट्रोल सिस्टम के साथ आइकॉनिक आर्किटेक्चर का दावा करती है। इसके ऑफिस का कैंपस 33,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। तीन अंडरग्राउंड लेवल्स में 400 गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेस है। अपनी डिज़ाइनिंग के लिए ही नहीं ये बिल्डिंग डिजाइनिंग अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है।

हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है इंग्लैंड का जुरासिक कोस्ट

इंग्लैंड के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है जुरासिक कोस्ट। हर साल यह दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। जुरासिक तट को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो अपनी उत्कृष्ट चट्टानों, जीवाश्मों और भू-आकृतियों के लिए पहचाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल की चट्टानें एक ही जगह पर देखी जा सकती हैं, जो कि 185 मिलियन वर्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं यहां रहने वाले विभिन्न प्राणियों के जीवाश्म अवशेषों को चट्टानों में संरक्षित किया गया है। जुरासिक तट दक्षिणी इंग्लैंड में 95 मील लंबा समुद्र तट है, जो डोर्सेट और डेवोन की काउंटी के भीतर स्थित है।

जमीन के अंदर शहर चट्टानों में बने चर्च

नजारा देखकर लगता है सपनों का संसार

चाहे कुदरत के बनाए नजारे हों, फिर जमीन के अंदर इंसानों की बसाए शहर या चट्टानों में काटे गए चर्च. तुर्की के कप्पाडोसिया में आकर आपको लगेगा कि आप किसी सपने के संसार में आ गए हैं. हैरान करने वाले कुदरती नजारे का साथ ही यह इतिहास और रहस्यों से भरपूर है.

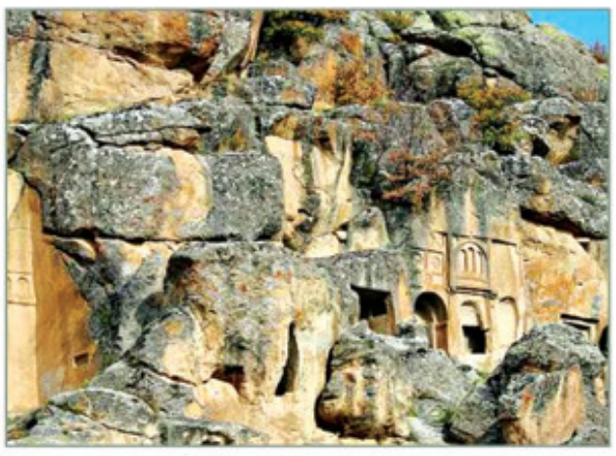

अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो एतिहासिक होने के साथ कुदरती खूबसूरती से भरी हो तो आपको को तुर्कीये के मध्य प्रांतो के उच्च पठार में मौजूद कप्पाडोसिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए. एक तरफ यहां की मनमोहक चिमनियां और प्राचीन चट्टानों की संरचनाएं हैं, तो वहीं दूसरी सांस्कृतिक विरासत भरे ऐसे इलाके भी हैं जहां गुफा चट्टान काट कर बने चर्च और भूमिगत शहर भी हैं.

लाखों साल पहले सेंट्रल एनाटोलियन क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोटों एक सिलसिला चला था. इसी के नतीजे में कैप्पाडोसिया फायरीज बनीं. यहां की मोटी राख जम कर टफ में और फिर उन खूबसूरत चिमनियों में बदल गई जिन्हें हम आज देखते हैं. लगभग 130 फीट ऊंचे ये टफ आने वाले कई सालों में आकार में बदल जाते हैं.

कप्पाडोसिया दुनिया में ईसाई धर्म के लिए सबसे अहम पूजा स्थलों में से एक है. 10वीं और 11वीं सदी के बीच, इस क्षेत्र में मठों और चट्टानों पर बहुत से चर्च बने. कई प्राचीन चर्च तो असाधारण आभूषणों से खूबसूरती से सजे हुए थे. यहां 600 से ज्यादा चर्च हैं, और और भी खोजे जा सकते हैं. इनमें से कुछ चर्चों के खूबसूरत भितिचित्र लोगों को काफी हैरान करते हैं.

कप्पाडोसिया का सबसे बड़ा आकर्षण यहां से की जाने वाली हॉट एयर बैलून से की जाने वाली सैर है. यह यहां की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है. यहां बाइकिंग और हाइकिंग के दौरान खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है. लेकिन कप्पाडोसिया हॉट एयर बैलूनिंग चमकदार प्राचीन नजारे देखने का सबसे अच्छा तरीका है.

कप्पाडोसिया के भूमिगत शहर इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान न चूकने वाले अनूठे अनुभवों में से एक हैं. इनमें से कुछ भूमिगत बस्तियां संकरी सुरंगों के एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं. इस क्षेत्र में लगभग 36 भूमिगत शहर हैं, कायमाली और डेरिनकुयू उनमें से सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर हैं.

ज्वालामुखी टफ की बदौलत, कप्पाडोसिया एक बड़ा अंगूर उत्पादक है और वाइन बनाने का एक लंबा इतिहास समेटे हुए है. इलाके की बाकी खूबियों के कारण टूरिस्ट भूल जाते हैं कि यह क्षेत्र अपनी वाइन के लिए भी जाना जाता है. यहां घूमने के लिए कुछ वाइनरी में कपाडोक्य, तुरासन, कोकाबाग और सेनल शामिल हैं. कुछ सबसे लोकप्रिय रेड और व्हाइट वाइन ब्रांड इस क्षेत्र से हैं, और पर्यटक वाइन-चखने वाली दुकानों में कुछ का नमूना ले सकते हैं.

कप्पाडोसिया अपने अविश्वसनीय ओपन-एयर संग्रहालय के लिए जाना जाता है, जो गोरेमे में मौजूद है. गोरेमे ओपन-एयर संग्रहालय इलाके में सबसे अधिक देखे जाने वाले और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है. क्षेत्र के अन्य रॉक साइट्स के अलावा, यह संग्रहालय तुर्कीये में पहला संग्रहालय था जिसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था.

क्या आप जानते हैं ट्रेनों पर लिखें नंबरों का मतलब

ट्रेन के नंबरों को ध्यान से देखें, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है ट्रेन के नंबर बोलते हैं। जी हां, ट्रेन के डिब्बों (बोगी) पर आपने नंबर लिखे देखे होंगे, आपको नहीं लगता कि ये आपको कुछ इशारा करते हैं। कभी मन में आपके ये सवाल भी उठे होंगे, लेकिन हाथों हाथ जवाब नहीं मिला होगा। यहां हम आपको ट्रेन के डिब्बों पर लिखे नंबरों का महत्व बताएंगे।

ट्रेन के डिब्बों पर लिखे नंबर आपको जानकारी ही नहीं देते बल्कि सुविधाजनक भी हैं। जैसे आपको बर्थ या सीट का नंबर टिकट पर लिखा मिलता है, जो आपको बताता है कि आप कहां बैठेंगे या लेटेंगे। ठीक वैसे ही डिब्बों पर लिखे इन अंकों में कई पहचान छिपी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि पांच अंक के ये नंबर इतिहास बताते हैं।

बोगी कितनी पुरानी है और कैटेगरी क्या है

किसी ट्रेन के डिब्बे पर लिखे नंबर की शुरुआत 04 या 99 है, तो आप समझ जाइये कि ये बोगी 2004 या 1999 में बनी है। आप जब स्टेशन पर कोई ट्रेन पकड़ने जाते हैं, तो बोगी पर लिखे नंबर पर आपका ध्यान जाता है, लेकिन आप पढ़कर भी नजर अंदाज कर देते हैं। अब आप नंबर पढ़ते ही पहचान जाएंगे कि ये नंबर आपसे क्या बोल रहे हैं। जैसे किसी ट्रेन के डिब्बे पर लिखे नंबर की शुरुआत 04 या 99 है, तो आप समझ जाइये कि ये बोगी 2004 या 1999 में बनी है। मतलब यह कि शुरुआती दो नंबर आपको बताते हैं कि बोगी कितनी पुरानी है। वहीं, इन दो नंबरों के बाद यदि 497 लिखा है, तो ये नंबर आपको बताते है कि ये जनरल बोगी या सामान्य डिब्बा है। रेलवे ने 497 कोड जनरल कैटेगरी के लिए तय किया हुआ है। और भी हैं कई कैटेगरी, नंबर जिन्हें देते हैं पहचान

ट्रेन में हर डिब्बे या बोगी की क्लास या कैटेगरी तय है। ट्रेन में हर डिब्बे या बोगी की क्लास या कैटेगरी तय है। आप इस कैटेगरी को नंबर के जरिए भी पहचान सकते हैं। बस आपको डिब्बे पर लिखी आखिरी तीन डिजिट ध्यान से देखनी होंगी। जैसे 001-025, ये नंबर बताते हैं कि ये फर्स्ट एसी के डिब्बे हैं। 026-050 ङ्क ये नंबर लिखे हों, तो समझ जाओ कि ये कंपोजिट फर्स्ट एसी या एसी-टूटी का डिब्बे हैं। 051-100 ये अंतिम तीन नंबर एसी-टूटी कोच को मिलते हैं। 101-150 ये नंबर बताते हैं कि ये डिब्बा एसी-थ्री को कैटिगराइज हैं। 151-200 यदि डिब्बे पर ये नंबर आखिरी में लिखे हों, तो पता चल जाता है कि ये डिब्बे सीसी या एसी चेयर कार के हैं। 201-400 नंबर सेकंड स्लीपर या एसएस कैटेगरी के कोच को दिए जाते हैं। कोच पर यदि ये 401-600 नंबर लिखे हों,तो इसका मतलब है कि ये जनरल सेकंड क्लास या जीएस के डिब्बे हैं। 601-700 अंतिम नंबर हों, तो ये डिब्बे सेकंड क्लास सिटिंग /जनशताब्दी चेयर कार यानी टूएस के कोच को दर्शाते हैं। 701-800 के नंबर के आखिरी तीन डिजिट हों, तो पता चलता है कि सिटिंग कम लगेज रेक्स हैं। यदि कोच पर 801 या इससे बड़े नंबर आखिरी तीन स्थान पर हों, तो पेंट्री कार, जेनरेटर और मेल के कोच की जानकारी देते हैं।

डिब्बे के रंग भी क्या कहते हैं जानेंज

डिब्बों के नंबर ही नहीं उनके रंग भी कई जानकारी देते हैं। किसी डिब्बे का रंग हरा होता है, तो किसी का नीला और किसी का लाल। डिब्बों या कोच के ये रंग ट्रेन की क्लास को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि रंग हर बार केवल क्लास ही बताते हैं। रंग ये भी बताते हैं कि ट्रेन किस फैक्ट्री में तैयार की गई है।

हाजीपुर स्थित कबीर मठ में स्थित एक ही कुएं में नौ प्रकार के स्वाद का पानी मिलता है। भारत के नक्शे पर छोटा सा दिखने वाला बिहार का हाजीपुर शहर एक कुएं के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। हाजीपुर स्थित कबीर मठ में स्थित इस एक ही कुएं में नौ प्रकार के स्वाद का पानी मिलता है। जी हां, इस कुएं के हर छोर के पानी का स्वाद अलग है। यही कारण है कि गंगा और गंडक के संगम पर स्थित इस कुएं को नवग्रह कुआं कहा जाता है।

भारत का सबसे चमत्कारी कुआं है यह, एक ही कुएं में मिलता है नौ तरह का पानी

प्रकृति का वरदान है नौ स्वाद वाले पानी का यह कुआं भारत चमत्कारों, रहस्यों और अद्भुत धरोहरों का संगम है। कुछ चमत्कार हमारे पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दिए तो कुछ प्रकृति ने वरदान के रूप में भेंट किए। यही कारण है कि भारत की धरती पर कदम कदम को आपको कुछ अनोखा देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही एक अजूबा है बिहार के हाजीपुर का एक छोटा सा कुआं। इस कुएं को प्रकृति का अनोखा वरदान कहा जा सकता है।

इसलिए बेहद अनोखा है यह कुआं

हाजीपुर स्थित कबीर मठ में स्थित इस एक ही कुएं में नौ प्रकार के स्वाद का पानी मिलता है। भारत के नक्शे पर छोटा सा दिखने वाला बिहार का हाजीपुर शहर एक कुएं के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। हाजीपुर स्थित कबीर मठ में स्थित इस एक ही कुएं में नौ प्रकार के स्वाद का पानी मिलता है। जी हां, इस कुएं के हर छोर के पानी का स्वाद अलग है। यही कारण है कि गंगा और गंडक के संगम पर स्थित इस कुएं को नवग्रह कुआं कहा जाता है। इस चमत्कारी कुएं को देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण साल 1640 में किया गया था। तभी से ये लोगों की आस्था का केंद्र है।

आज तक नहीं सुलझ पाया यह रहस्य

इस कुएं के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते हैं। इस कुएं और नदी के बीच की दूरी करीब 100 फीट है। इसके बाद भी कुएं का जलस्तर नदी के जलस्तर से हमेशा ऊंचा रहता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसका रहस्य आजकल नहीं सुलझ पाया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं पर कभी भी किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं पड़ा है। 383 साल से यह कुंआ यहां शान से है। यहां प्रतिवर्ष विश्वप्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान लोग अपने ग्रहों की शांति के लिए इस कुएं की पूजा करना नहीं भूलते। कहते हैं यहां पूजा के बाद लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं।

शोधकर्ताओं ने खोज निकाला सच

कुएं के नौ अलग-अलग मुहाने के पानी में नौ प्रकार के मिनरल हैं। यही कारण है कि इसका स्वाद अलग-अलग है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कुआं नवग्रहों की गति को सुधार देता है। कोई भी दोष होता है, उसे दूर कर देता है। यही कारण है कि प्रतिदिन यहां लोग ग्रहों की शांति की पूजा करने आते हैं और कुएं के अलग अलग स्वाद के पानी का सेवन करते हैं। एक ही कुएं में इस तरह नौ स्वाद का पानी आना लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं है। यही कारण है कि देश विदेश के शोधकर्ता यहां इस रहस्य को सुलझाने आए। शोधकर्ताओं ने भी माना है कि इस कुएं का पानी नौ अलग अलग स्वाद का है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि कुएं के नौ अलग-अलग मुहाने के पानी में नौ प्रकार के मिनरल हैं। यही कारण है कि इसका स्वाद अलग-अलग है। कारण कुछ भी हो लोग इस कुएं को ईश्वर के वरदान के रूप में ही देखते हैं। उनका मानना है कि हर ग्रह एक अलग स्वाद के पानी का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पाकिस्तान ने मोदी को दिया एससीओ सम्मेलन का निमंत्रण

नई दिल्ली। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) की बैठक होने वाली है। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान ने अन्य नेताओं के साथ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण एससीओ के दूसरे सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, सीएचजी की अध्यक्षता में पाकिस्तान के रोटेशन का अनुसरण करता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण यह संभावना नहीं है कि मोदी इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के बिश्केक में सीएचजी बैठक में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी, जो नियमित रूप से एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, संसद सत्र के कारण इस साल कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। रूस और चीन के नेतृत्व वाला एससीओ क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।

योगी ने एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी की सराहना की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन और उज्ज्वल भविष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने विज्ञान धारा योजना कोमंत्रिमंडल की मंजूरी की भी सराहना की और कहा कि इस पहल से देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। बायोई3 नीति को मंजूरी देने केमंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, यह नीति अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे हमें जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यूपीएस को मंजूरी देने केमंत्रिमंडल के फैसले की सराहना करते हुए आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 140 करोड़ देश वासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।

एकीकृत पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस का तंज

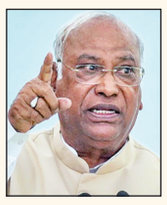

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है। विपक्षी पार्टी ने यह कटाक्ष ऐसे समय किया गया है, जब शनिवार को ही केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंश योजना का एलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जनवरी, 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को यूपीएस योजना का लाभ मिलेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को वेतन के 50 प्रतिशत की बराबर पेंशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। यूपीएस को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है! 4 जून के बाद, प्रधानमंत्री की सत्ता के अहंकार पर लोगों की शक्ति हावी हो गई है।

विधानसभा चुनाव से पहले आप के पांच पार्षद भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के पांच पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में आप पार्षद भाजपा में शामिल हुए। रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पांच पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों में वार्ड 178 से सुगंधा बिधूड़ी, वार्ड 28 से राम चन्द्र, वार्ड 30 से पवन सहरावत, वार्ड 180 से मंजू निर्मल, वार्ड 177 से ममता पवन शामिल हैं।

हरियाणा विस चुनाव की तारीखों में हो सकता है बदलाव

हिसार। हरियाणा में आगामी चुनावों की तारीखों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, अब चुनाव सात या आठ अक्तूबर को हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है, जिसके बाद चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है। इस संबंध में मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग के संभावित निर्णय का सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनावी रणनीतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें मंगलवार को होने वाली घोषणा पर टिकी हैं, जिसमें यह साफ हो सकेगा कि हरियाणा के मतदाता किस दिन अपना वोट डालेंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने तर्क दिया है कि एक अक्तूबर के आसपास वीकेंड व छुट्टियां हैं। इस कारण लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर पड़ सकता है।

मायावती का राहुल गांधी से सवाल

कांग्रेस सालों तक सत्ता में रही क्यों नहीं कराई जाति जनगणना

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को लेकर कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी (सपा) पर रविवार को तंज कसते हुए उन्हें ''दोगली सोच'' वाले दल बताया और लोगों से उनके ''चाल और चरित्र को लेकर सजग'' रहने को कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी सपा एवं कांग्रेस जैसे दलों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी।

मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''कल (शनिवार) प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते-जी एवं उनके देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया।''

मायावती ने कहा, ''बाबा साहेब के अभियान को गति देने वाले मान्यवर कांशीराम का देहांत होने पर भी इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और न ही तत्कालीन सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहें।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना मामले में सवाल उठाते हुए कहा, ''केंद्र में भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई थी जबकि अब वह इसकी बात कर रही है, जवाब दें? बसपा हमेशा ही इसकी पक्षधर रही है, क्योंकि यह कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है।'' राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि देश के 90 प्रतिशत लोग व्यवस्था से बाहर हैं और उनके हित में कदम उठाये जाने की जरूरत है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था, ''कांग्रेस के लिए जातिगत जनगणना नीति निर्माण की बुनियाद है। मायावती ने कहा, ''इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व 'क्रीमी लेयर' के जरिये इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि ने चुप्पी साध रखी है। क्या यही इनका दलित प्रेम है, सचेत रहें।

बसपा प्रमुख ने कहा, ''सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन करना क्या एससी, एसटी व ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के हित में उचित होगा। यह कतई नहीं होगा। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक की ''आपत्तिजनक टिप्पणियों'' पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि सार्वजनिक रूप से दिये गये इस वक्तव्य के लिए विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। इस मामले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के प्रति आभार जताया था।

सपा और बसपा एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। हालांकि 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव में समझौता हुआ था तब यह पहल बसपा संस्थापक कांशीराम और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने की थी। जून 1995 में लखनऊ के सरकारी अतिथि गृह में सपा और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों के बाद यह समझौता टूट गया था।

महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचकर लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मलेन में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने कई 'लखपति दीदियों' से बातचीत की। इसके अलावा पीएम ने 2,500 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज यहां लखपति दीदी का महासम्मेलन हो रहा है। मेरी बहनें यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। आज यहां से देशभर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6 हजार करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। मेरी सभी माताओं-बहनों को बहुत-बहुत शुभेच्छा।% उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में माताओं-बहनों के लिए, नौजवानों और किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई-नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान, सिर्फ बहनों-बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। बीते 10 वर्षों में एक करोड़ लखपति दीदी बनीं और बीते सिर्फ दो महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गईं। उन्होंने आगे कहा कि पहले देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में वो कोई भी छोटा-मोटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती थीं। इसलिए आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए- मेरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए।

अपनी पोलैंड यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से कहा, पोलैंड के लोग, महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल, कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान, पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी।

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आज चुनौती देता हूं- पहले की सरकारों के सात दशक एक तरफ रख लीजिए और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल रख लीजिए, जितना काम मोदी सरकार ने देश के बहन-बेटियों के लिया किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है।

अपनी सरकार के किए कामों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, %ये हमारी सरकार ने तय किया कि जो गरीबों के घर सरकार बनाती है तो वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हों। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं, वो अधिकतर महिलाओं के नाम पर हैं। अभी हम 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं, इनमें से भी अधिकतर घर हमारे माताओं-बहनों के नाम पर ही होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार, बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है, जहां कभी उन पर पाबंदियां थीं। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं, फाइटर पायलट तैनात हो रही हैं। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर, स्टार्ट अप्स क्रांति तक, आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा, आज सवा लाख से अधिक बैंक सखियां, गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। अब हम बहनों को ड्रोन पायलट भी बना रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनिक खेती करने में किसानों की मदद कर पाएं। आधुनिक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए हम नारीशक्ति को नेतृत्व दे रहे हैं, इसके लिए हमने कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है।

बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि 21वीं सदी में भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो 'विकसित भारत' की नींव को मजबूत कर रहा है। उन्होंने अपने मासिक 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में कहा कि उनकी ओर से स्वतंत्रता दिवस पर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं के राजनीति में शामिल होने के आह्वान पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली है।

उन्होंने युवाओं से विकसित भारत तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक जीवन में आने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेक लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

मोदी ने कहा, ''इन लोगों ने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी भावना की जरूरत है।''

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं और बस उन्हें सही मौके तथा सही मार्गदर्शन की तलाश है। मोदी ने कहा कि उनके इस आह्वान पर युवाओं ने उन्हें पत्र लिखे हैं और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा है कि परिवारवाद की राजनीति नयी प्रतिभा को दबा देती है। कार्यक्रम के दौरान, मोदी ने विभिन्न अंतरिक्ष स्टार्ट-अप का नेतृत्व करने वाले कई युवा उद्यमियों से बात की और युवा उद्यमियों ने अपने काम पर प्रकाश डाला।

उन्होंने देश में बढ़ते जीवंत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न सुधारों से काफी फायदा मिला है।

उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। मोदी ने पर्यावरण में सुधार लाने में विभिन्न संगठनों और लोगों के काम पर प्रकाश डालते हुए इस क्षेत्र में सामूहिक प्रयास पर जोर दिया।

खेल
प्रमुख समाचार

23 साल में पहली बार बांग्लादेश से टेस्ट में हारा पाकिस्तान

रावलपिंडी। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने पहली पारी में छह विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश ने 565 रन बनाए और 117 रन की बढ़त हासिल की। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में पाकिस्तान को 146 रन पर समेट दिया। 30 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 10 विकेट रहते हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला टेस्ट 29 अगस्त 2001 से खेला गया था। करीब 23 साल में यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट में हराया है। इस बीच दोनों देशों के बीच 14 टेस्ट खेले गए हैं और 12 टेस्ट पाकिस्तान ने जीते हैं। एक बांग्लादेश ने जीता है और एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। वहीं, पाकिस्तान की यह अपने घर में एक और शर्मनाक हार है। टीम चार मार्च 2022 के बाद अपने घर में नौ टेस्ट खेल चुकी है और पांच मुकाबले हार चुकी है। चार टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। टीम ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट ड्रॉ कराए हैं, जबकि एक में हारी है। वहीं, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की दो टेस्ट मैचों की सीरीज ड्रॉ रही थी। अब अपने घर में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यह बांग्लादेश में अस्थिरता के बाद उनकी क्रिकेट टीम का पहला विदेशी दौरा था और उसी में टीम ने इतिहास रच दिया है। नजमुल शांती की अगुआई में गजब का प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत हासिल कर अपने देश के लोगों को खुशी दी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत नवंबर में

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत नवंबर में कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह कहा। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में लागू किया। और अब वे इसका दायरा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए (व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता) वार्ता का दसवां दौर 19-22 अगस्त को सिडनी में हुआ। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, वस्तु उत्पत्ति के नियम और कृषि-तकनीक के क्षेत्रों पर बातचीत हुई। बयान के अनुसार इनमें से प्रत्येक विषय पर दोनों पक्षों ने गहन चर्चा की। मंत्रालय ने बयान में कहा, ''सीईसीए वार्ता का अगला दौर नवंबर में होने की संभावना है।'' भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के मुख्य वार्ताकार और अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने किया।

विदेशी निवेशकों ने बॉन्ड बाजार में 11,366 करोड़ रुपये लगाए

नईदिल्ली। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक देश के बॉन्ड बाजार में 11,366 करोड़ रुपये लगाये हैं। इसके साथ बॉन्ड क्षेत्र में शुद्ध रूप से पूंजी प्रवाह इस साल एक लाख करोड़ रुपये का पार कर गया है। भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की मजबूत खरीदारी का कारण इस साल जून में जेपी मॉर्गन के उभरता बाजार सरकारी बॉन्ड सूचकांक में भारत को शामिल किये जाने को दिया जा सकता है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने (24 अगस्त तक) बॉन्ड बाजार में 11,366 करोड़ रुपये लगाये हैं। भारतीय बॉन्ड बाजार में जुलाई में 22,363 करोड़ रुपये, जून में 14,955 करोड़ रुपये और मई में 8,760 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश हुए थे। इससे पहले, उन्होंने अप्रैल में 10,949 करोड़ रुपये निकाले थे।

अगले हफ्ते 9 कंपनियों के आएंगे आईपीओ

नई दिल्ली। अगर आप आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अगला हफ्ता आपके लिए है। अगले हफ्ते 9 कंपनियों अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। जो आईपीओ अगले हफ्ते मार्केट में आएंगे, उनमें मेन बोर्ड और एसएमई बोर्ड, दोनों के शामिल हैं। मेनबोर्ड सेगमेंट में इकोस मोबिलिटी, प्रीमियर एनर्जीज और बाजार स्टाइल रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए अपने पब्लिक ऑफरिंग खोलेंगी। इनके अलावा छह और कंपनियां एसएमई सेगमेंट में अपने इश्यू लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वहीं 8 आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे। इनमें ओरिएंट टेक्नोलॉजीज और इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक आईपीओ पर कड़ी नजर रखते हैं। इसका कारण है कि अगर आईपीओ अलॉट हो जाए तो कई बार ये कम समय में अच्छा रिटर्न दे देते हैं। कई आईपीओ तो लिस्टिंग के समय दोगुने तक का रिटर्न दे चुके हैं।

घरेलू आय में कमी को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उसने रविवार को दावा किया कि वेतन वृद्धि की धीमी गति और कमरतोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी में अभूतपूर्व गिरावट आई है। सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह सरकार भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी सबसे बुनियादी चुनौती के प्रति आंखें बंद किए हुए है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक जाने माने ब्रोकरेज फर्म की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर उस सच्चाई पर प्रकाश डाला है, जिसे केंद्र सरकार लगातार नकारती रही है कि भारत में वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है। धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी (महंगाई के हिसाब से समायोजित वेतन) या कहें कि आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है।

सुखद है भारतीय स्टार्टअप की घर वापसी

डॉ. अश्विनी

ऐसी खबरें आयी हैं कि कई भारतीय स्टार्टअप, जो पहले विदेशों में फ्लिप कर गये गये थे, अब भारत लौट रहे हैं। किसी भारतीय कंपनी के फ्लिपिंग का मतलब है, एक ऐसा लेन-देन जिसमें प्रमोटर किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में अपनी कंपनी को पंजीकृत करता है, जिसे फिर भारत में स्टार्टअप कंपनी की होल्डिंग कंपनी बना दी जाती है। परिणामस्वरूप, भारतीय स्टार्टअप का अंतिम स्वामित्व विदेशी क्षेत्राधिकार में चला जाता है। इसलिए रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ है, वे स्टार्टअप जिन्होंने अपनी मालिकाना कंपनियों को विदेशी क्षेत्राधिकार में शामिल किया था, वे स्वामित्व को वापस भारत ला रहे हैं। जिन महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स ने वापस फ्लिप किया है, उनमें फोन पे और ग्रो शामिल हैं। फ्लिपकार्ट के साथ ही जेप्टो और रेजर पे भी वापस फ्लिप करने का प्रयास कर रहे हैं।

फ्लिप करने वालों के पसंदीदा गंतव्य सिंगापुर, मॉरीशस, केमैन आइलैंड और ब्रिटेन थे। जबकि भारतीय स्टार्टअप फ्लिपिंग के माध्यम से भारत के विनियामक दायरे से बाहर हो गये थे, उन्होंने अब एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' के माध्यम से भारतीय विनियामक ढांचे के तहत आना चुना है। फ्लिप करने वाले स्टार्टअप वे हैं जिनके प्रमोटर भारत से हैं और उन्होंने भारतीय संसाधनों- मानव, पूंजी और सरकारी सहायता से अपना कारोबार खड़ा किया।

उनके फ्लिप करने का पहला कारण है कि वे भारतीय नियामक प्रणाली, भारतीय कर कानूनों और भारतीय अधिकारियों की जांच से बचना चाहते थे। दूसरा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निवेशक उन कंपनियों को विदेश

में फ्लिप करने के लिए मजबूर करते हैं जहां वे अपना पैसा लगाते हैं। तीसरा, अमेरिका, सिंगापुर जैसे कई देशों ने स्टार्टअप और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अनुकूल नीतियां बनायी हैं।

चौथा, ये स्टार्टअप अपने शेयरों को विदेश में सूचीबद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभिनव विचारों को बेहतर मूल्यांकन मिलता है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एक ऐसा मॉडल है जिसने कई स्टार्टअप को अपनी होल्डिंग कंपनियों को अमेरिका में सूचीबद्ध करने के लिए आकर्षित किया है। पांचवां, कराधान के मामले में भारतीय घरेलू निवेशकों के लिए समान अवसर की कमी, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारतीय निवेशकों की तुलना में अधिक लाभ उठाया। भारत से कंपनियों के फ्लिपिंग का पहला और सबसे बड़ा नुकसान संपत्ति और आय पैदा करने वाली संपत्ति का है। जब कोई भारतीय कंपनी विदेशी क्षेत्राधिकार में शामिल किसी कंपनी की सहायक कंपनी या एक विदेशी कंपनी बन जाती है, तो सरकार न केवल पूंजीगत लाभ कर राजस्व का अवसर खो देती है, बल्कि स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी की लिस्टिंग से संभावित पूंजी निर्माण से भी वंचित हो जाती है। दूसरा, देश की बौद्धिक संपदा विदेशी देशों को हस्तांतरित हो जाती है और डेटा पर अधिकार भी विदेशियों को मिल जाता है। बौद्धिक संपदा में भविष्य की वृद्धि और विस्तार के सभी लाभ भी विदेशी देशों को हस्तांतरित हो जाते हैं। तीसरा, फ्लिप करने वाले स्टार्टअप भारतीय कर क्षेत्राधिकार और अन्य विनियामक ढांचे से बाहर हो जाते हैं और इस तरह वे अपने भारतीय समकक्षों पर बढ़त हासिल कर लेते हैं। चौथा, चूंकि फ्लिप किये गये स्टार्टअप का मुख्यालय विदेश में होता है, इसलिए उनके फंड के स्रोत को जानना मुश्किल हो जाता है। यह देश के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। पांचवां, हमारे स्टार्टअप के फ्लिप करने का नुकसान यह भी है कि इससे भारतीय शेयर बाजार की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।सरकार का दावा है कि भारत की मजबूत वृद्धि घरेलू स्टार्टअप के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' की प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, जो कभी पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश जाते थे, अब घर लौट रहे हैं। विकास और तकनीकी विकास के साथ, कई अन्य कारण भी हैं, जो इस रिवर्स फ्लिपिंग को चलाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने 'पीपुल फॉर पीपल' अभियान का किया शुभारंभ

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पीपल के पौधे का किया रोपण
नवा रायपुर में 204.84 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

रायपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा परिसर में ''पीपुल फॉर पीपल'' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204.84 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, खेल युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्व श्री राजेश मूणत, किरण देव, पुरंदर मिश्रा, इंद्रकुमार साहू, मोती लाल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एक लाख पौधों का होगा रोपण

नवा रायपुर अटल नगर द्वारा ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान अंतर्गत ''पीपुल फॉर पीपल'' कार्यक्रम में एक लाख से अधिक स्थानीय प्रजाति के बड़े पेड़ रोपे जाएंगे। वर्तमान में 21,000 से अधिक पीपल के वृक्ष लगाये जा चुके हैं। नवा रायपुर अटल नगर का लक्ष्य है कि शहर में किसी भी स्थान पर खड़े होने पर पीपल का वृक्ष दिखाई दे। पीपल के वृक्ष के संबंध में श्रीमद भगवद्गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ''वृक्षों में मैं पीपल हूं।'' पीपल का वृक्ष 100 वर्षों से अधिक एवं 24 घण्टे जीवनदायिनी वायु प्रदान करने वाला वृक्ष है। कार्यक्रम अंतर्गत युवाओं को जोड़ने एवं जन सुविधा हेतु मोबाईल एप के माध्यम से ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान अंतर्गत ''पीपुल फॉर पीपल'' में वर्चुअल एडॉप्शन की सुविधा का उपयोग कर 2000 से ज्यादा जन सामान्य सहभागी भी बन चुके हैं।

रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग

नवा रायपुर अटल नगर से अन्य शहरों की कनेक्टीविटी के लिए बिछाई गई रेलवे लाईन में शहर के मध्य रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। यह स्टेशन 75 करोड़ रूपए की लागत से तैयार की गई है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 रेलवे स्टेशन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

नवा रायपुर अटल नगर में लगभग 5.3 किलोमीटर में स्मार्ट सडक एवं अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण 35.25 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है। 100 बस के अतिरिक्त 148 कार, टैक्सी और लगभग 250 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा 23.12 करोड़ रूपए की लागत से विकसित की गई है।

राखी गांव में विश्वस्तरीय स्मार्ट शैक्षणिक व्यवस्था की सुविधा एवं वृहद बहुद्देशीय सभागार प्रदान करने के लिए 18 करोड़ रूपए हायर सेकेण्डरी स्कूल तैयार किया गया है। इससे 1200 से ज्यादा बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा का माहौल मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु 11 करोड़ रूपए की लगात से भवन निर्मित किया गया है। इस स्कूल में 950 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नवा रायपुर अटल नगर के 11 ग्रामों में 10.35 करोड़ रूपए की लागत से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन किया गया है, जिससे लगभग 4300 स्कूली बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।

बागवानी कार्य में जल निकायों का विकास के लिए 16 करोड़ रूपए की लागत से मंत्रालय के निकट जल संवर्धन, नालों, तालाबों को पुनर्जीवित करना एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इसके अलावा वर्षा जल की प्राकृतिक धाराओं को विकसित कर भू-जल स्तर को बढाने के लिए 16.12 करोड़ रूपए की लागत से आवश्यक कार्य एवं नये तालाबों का निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्य किये गये है।

एजुकेशन हब नरदहा में शराब कोचियों का बोलबाला , ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

रायपुर । एजुकेशन हब के नाम से विख्यात विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नरदहा में शराब कोचियों का बोलबाला है । ग्रामीणों व पंचायत के लगातार मनाही के बाद भी बाज न आने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव के बाद ग्रामवासियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । मोर्चा के प्रथम चरण में ग्रामसभा का प्रस्ताव ले पंचायत प्रतिनिधियों , शाला विकास समिति , महिला संगठनों सहित प्रबुद्ध ग्रामीणों ने पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा , पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह , थाना प्रभारी मुकेश वर्मा को ज्ञापन सौंप अवैध शराब बिक्री पर स्थायी रोक लगाने व लिप्त तत्वों के खिलाफ ठोस व प्रभावी कार्यवाही की मांग की है । ज्ञापन की प्रति क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह व शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा

को भी सौंप सहयोग का आग्रह किया गया है । विधानसभा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर - बलौदाबाजार मार्ग पर स्थित है तकरीबन 8000 की आबादी वाला ग्राम नरदहा जो एजुकेशन हब के नाम से विख्यात है । शहरी परिवेश से जुड़ जाने के चलते यहां की ग्रामीण व्यवस्था चरमरा गया है और इसी के चलते ग्रामीणों व पंचायत के मनाही के बाद भी असमाजिक तत्व यहां हावी हो चले हैं जिसका खामियाजा ग्राम के सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों को अशांति के रूप में भुगतना पड़ रहा है । इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बीते 20 अगस्त को आयोजित ग्रामसभा की बैठक में अवैध शराब बिक्री स्थायी रुप से बंद कराने शासन -प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने व असफलता की स्थिति में आंदोलनात्मक रुख अपनाने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है । इसी प्रस्ताव के अनुरूप ग्राम के एक प्रतिनिधि मंडल ने आई जी , एस पी व थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन उनके केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते उनके कार्यालय को सौंपा है ।

मोदी ने कोरिया मिलेट्स कैफे की सफलता पर जताई खुशी, लखपति दीदी हीना के लिए बजवाई ताली

रायपुर। कोरिया जिले में परम्परागत खाद्यान को लेकर समूह की दीदियां जिस तरह से मिलेट्स कैफे का संचालन कर रही हैं, यह हमारी बहनो की मेहनत और सफलता के लिए एक नई इबारत लिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में कोरिया मिलेट्स कैफे की खुलकर तारीफ की। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लखपति दीदी

सम्मेलन में कोरिया जिले में ग्राम पंचायत पटना के रोशनी स्व सहायता समूह की हीना बेगम से संवाद किया और उनके सामूहिक सफलता के लिए उपस्थित जनसमूह से तालियां बजवाईं। कोरिया जिले में महिलाओं के स्व सहायता समूहों की सफलता की कड़ी में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। लखपति दीदी के रूप में कोरिया मिलेट्स कैफे की संचालक हीना बेगम को आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का अवसर मिला और मोदी ने हीना से आत्मीय बातचीत की। सबसे पहले मोदी ने हीना से उनका परिचय प्राप्त किया। फिर उनके काम करने के बारे में विस्तार से जानकारी ली। हीना बेगम ने उन्हें बताया कि हमारे रोशनी स्व सहायता समूह के द्वारा 4 अन्य समूहों के साथ मिलकर मिलेट्स कैफे का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीना से कैफे द्वारा अर्जित आय और मिलेट्स कि उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह रायपुर के 3 दिवसीय प्रवास के बाद नई दिल्ली रवाना

रायपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 3 दिवसीय प्रवास के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर अमित शाह को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा, श्री राजेश मूणत, धरम लाल कौशिक, अमर अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाव-भीनी विदाई दी।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

ाबालिग की हत्या के 3 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ॅबिलासपुर। न्यायधानी के तारबाहर क्षेत्र में दो साल पहले हुए ऑटो डीलर के नाबालिग बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। तारबाहर निवासी 15 वर्षीय मोहम्मद रेहान 6 फरवरी 2022 को शाम करीब 5.30 बजे अपनी मां से पैसे लेकर चिप्स खरीदने के लिए खुदीराम बोस चौक, डीपूपारा की एक किराना दुकान गया था। इसी दौरान तारबाहर निवासी अभिषेक दान, देवनगर कोनी के साहिल उर्फ शीबू खान और रवि खांडेकर ने उसका अपहरण कर लिया। जब देर रात तक रेहान घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और तारबाहर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात करीब 11.30 बजे रेहान के पिता मोहम्मद आसिफ के मोबाइल पर रेहान के नंबर से कॉल आया। आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया और अभिषेक दान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दो साथियों, साहिल और रवि को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रेहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को एक बोरी में भरकर रतनपुर हाइवे पर मदनपुर के पास एक पुल के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थान से रेहान का शव बरामद किया। मामले की

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण हमें जीवन जीने का सही राह बताते हैं। उनके उपदेश जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री ने भारतरत्न मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें किया नमन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारतरत्न मदर टेरेसा की जयंती 26 अगस्त पर उन्हें नमन किया है। मदर टेरेसा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि मदर टेरेसा ने मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दीन-दुखियों,अनाथ और असहाय लोगों का सहारा बनकर पूरी दुनिया को सेवा और शांति का पाठ पढ़ाया। उनके स्नेह और समर्पण के कारण लोगों ने उन्हें मदर का दर्जा दिया। सेवा के क्षेत्र में वह इतनी ऊंची उठ गई कि उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री साय ने कहा कि मदर टेरेसा का जीवन हमेशा लोगों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरणा देता रहेगा।

पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, मोड़ पर मिली लाश

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक पुलिसकर्मी की अचेत अवस्था में लाश मिली

है. लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर जांच में जुट गई है. यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है. महासमुंद के तुमगांव थाना में पदस्थ कांस्टेबल रोहित चंद्राकर की आज सुबह मौत हो गई. कांस्टेबल रोहित हर रोज की तरह आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उन्हें खरोरा सरारडीह मोड़ पर अचेत अवस्था में पाया गया. यह घटना सुबह 6 से 7 बजे के बीच की है. मृतक कांस्टेबल के चेहरे और माथे पर चोट के निशान भी मिले हैं. प्रथम दृष्टया मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा. जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल रोहित चंद्राकर 47 वर्ष के थे और उनके दो बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटे की शादी हो चुकी है. वे खरोरा के निवासी थे और पिछले 14 वर्षों से पुलिस सेवा में कार्यरत थे.

डीएफओ की अनूठी पहल, चलाया महुआ बचाओ अभियान

रायपुर। महुआ पेड़ो की घटती संख्या चिंता का विषय है। सबसे बड़ी समस्या इनकी पुनरुत्पादन की है। जंगल में तो महुआ पर्याप्त है पर आदिवासियो के द्वारा अधिक्तर महुआ का संग्रहण गाँव के ख़ाली पड़े ज़मीन और खेत के मेड़ो पे लगे महुआ से होती है। अगर आप बस्तर और सरगुज़ा के किसी गाँव में जाये तो उनके खेतों के पार और ख़ाली ज़मीन में सिर्फ़ बड़े महुआ के पेड़ ही बचे दिखते है। छोटे और मध्यम आयु के पेड़ लगभग नगण्य होती हैं। ग्रामीणों के द्वारा महुआ संग्रहण से पहले ज़मीन साफ़ करने हेतु आग लगाई जाती है उसी के कारण एक भी महुआ के पौधे ज़िंदा नहीं रहते। ग्रामीण महुआ के सभी बीज को भी संग्रहण कर लेते है।ये भी एक कारण है महुआ के ख़त्म होने का।आख़रि बड़े महुआ पेड़ कब तक जीवित रह पायेंगे। छत्तीसगढ़ के महुआ पेड़ बूढ़े हो रहे है।महुआ पेड़ की औसत आयु 60 वर्ष है ।अगर जंगल के बाहर इनके पुनरुत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएँगे। मनेंद्रगढ़ वनमण्डल में इस वर्ष वनमंडलधिकारी मनीष कश्यप के पहल से पहली बार गाँव के बाहर ख़ाली पड़े ज़मीन और खेतों में महुआ के पौधे लगाये जा रहे है.

अण्णा भाऊ साठे की 104 वीं जयंती समारोह में शामिल हुए सांसद अग्रवाल

रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल रविवार को राजधानी के कांशीराम नगर में छत्तीसगढ़ मांग समाज द्वारा लोक शाहीर साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे की 104 वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अण्णा भाऊ साठे को नमन करते हुए उनके कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि अण्णा भाऊ साठे ने लोगों को एकजुट करने के साथ ही लोगों को शिक्षा की अहमियत बताई थी। साठे ने सामाजिक कुरीतियां के विरोध में समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया था और गरीबों के उत्थान के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को समाज हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर सांसद अग्रवाल ने क्षेत्र में सामुदायिक भवन में अतिरिक्त भवन निर्माण और रखरखाव के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में पार्षद श्रीमती शीतल कुलदीप बोगा, रमेश जाधव, राकेश खंदार, संजय जाधव, शंभू वाबने, प्रदीप जाधव समेत समाज के लोग उपस्थित रहे।

नंदनवन जंगल सफारी में तितलियों पर हुआ वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन

रंग-बिरंगी तितलियों की जानकारी रहा आकर्षण का केंद्र

रायपुर। राजधानी रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में 24 अगस्त को तितलियों पर वॉक एंड टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रायपुर, कुरुद और बिलासपुर के विभिन्न कॉलेजों से 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

वॉक एंड टॉक कार्यक्रम की शुरुआत में कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री जे.पी. टंडन ने विद्यार्थियों को तितलियों की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। इसके पश्चात शासकीय साइंस कॉलेज रायपुर के जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. कविता दास ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि अत्याधिक कीटनाशकों के उपयोग के कारण तितलियों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है, जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने

विद्यार्थियों को इस दिशा में संवेदनशीलता विकसित करने और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में इसके बाद विद्यार्थियों के वॉक की शुरुआत हुई, जिसमें छात्रों को दो समूहों में बाँटा गया। वॉक के दौरान उन्होंने 3 किलोमीटर के ट्रेल पर तितलियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की। इस दौरान छात्रों ने कॉमन क्रो, एमिग्रेंट, ग्रेट एगफ्लाई, सेलर जैसी तितलियों को देखा।

वॉक के अंत में, सभी विद्यार्थी जू कैंपस में स्थित बटरफ्लाई गार्डन पहुँचे, जहाँ उन्हें होस्ट प्लांट्स के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि तितलियों के जीवनचक्र में इन पौधों की क्या भूमिका होती है और कौन से पौधे तितलियों के जीवित रहने में अहम भूमिका निभाते है । भ्रमण के उपरांत विद्यार्थियों को इंटरप्रिटेशन हॉल में जंगल सफारी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वॉक एंड टॉक कार्यक्रम में नंदनवन जंगल सफारी के निदेशक श्री धम्मशील गणवीर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल सफारी को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहाँ विद्यार्थी वन्यजीवों पर शोध और अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकें।

उन्होंने विद्यार्थियों को जंगल सफारी में युवान वालंटियर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भी अपील की कार्यक्रम अंत में सभी विद्यार्थियों को उनकी भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें चिड़ियाघर का भ्रमण कराया गया। जहाँ उन्होंने तितलियों और अन्य जीवों को नजदीक से देखा।

विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन, सिटी कोतवाली का किया घेराव

रायपुर/महासमुंद। बलोदा बाजार हिंसा मामले में आज भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने जेल भरो आंदोलन रैली का आयोजन किया. रैली के दौरान कांग्रेस भवन से निकल कर युवक कांग्रेसी सिटी कोतवाली पहुंचे और मुख्य गेट को घेर लिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झुमा-झटकी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में बंद कर दिया. हालांकि घंटे भर के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

बता दें, कोतवाली में पहले से ही पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात थी, जिससे युवक कांग्रेसी को परिसर में प्रवेश नहीं मिल सका. इसके बावजूद, पुलिस और युवक कांग्रेसियों के बीच झुमा झटकी की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने सभी युवक कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर मिनी स्टेडियम में बनाए गए अस्थाई जेल में घंटे भर रखा. सभी को फिर बाद में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया. युवक कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के इशारे पर देवेन्द्र यादव को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है. युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव निखिलकांत साहू ने कहा कि भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. हम इसका विरोध करते हैं.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.